वर्ष 12 • अंक 240 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 26 नवंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

मौसम की मार से पिछड़ी रबी की बुआई

सुरेश नारायणन ▶▶ पृष्ठ 2

खपत में नरमी, ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर

डॉलर रु. 71.70 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 79.00 ▼ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37871 ▼ 286 रुपये | सेंसेक्स 40889.20 ▲ 529.80 | निफ्टी 12073.80 ▲ 159.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 12141.60 ▲ 67.80 | ब्रेंट क्रूड 62.90 डॉलर ▼ 0.10 डॉलर

एक नज़र

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर फैसला आज

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे अपना आदेश सुनाएगा। शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस ने सोमवार को ही देवेंद्र फडणवीस को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश देने का अनुरोध किया लेकिन फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसका विरोध किया। राज्यपाल कोश्यारी ने 23 नवंबर को जब फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी तो उन्हें अपना बहुमत साबित करने के लिए 14 दिन का समय दिया था। दूसरी तरफ राज्य में सोमवार को भी राजनीतिक हलचल तेज रही और दोनों पक्ष बहुमत होने का दावा करते नजर आए। इस बीच,महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को बताया कि उसने राज्य की 9 सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच बंद कर दी है। एजेंसी ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि ये मामले उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े हुए नहीं हैं। पृष्ठ 14

चंद्रा का ज़ी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफा

ज़ी एंटरटेनमेंट (जेडईईएल) के प्रवर्तक सुभाष चंद्रा ने कंपनी के चेयरमैन पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया। जेडईईएल ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह सेबी सूचीबद्धता नियमन के नियम 17 (आईबी) के अनुरूप है। इसके अनुसार निदेशक मंडल का चेयरमैन, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। चंद्रा कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक बने रहेंगे।

सीबीएस बैंक के आईपीओ को 4.35 गुना आवेदन

सीबीएस बैंक के आईपीओ को दूसरे दिन सोमवार को 4.35 गुना आवेदन मिले। बैंक के 1.15 करोड़ शेयरों के लिए 5 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। पात्र संस्थागत खरीदार श्रेणी के लिए रखे गए शेयरों को 26 फीसदी जबकि गैर-संस्थागत निवेशक श्रेणी में पूरा अभिदान मिला। खुदरा निवेशक श्रेणी में 21.53 गुना आवेदन प्राप्त हुए। सीबीएस बैंक ने गुरुवार को एंकर निवेशकों से 184 करोड़ रुपये जुटाए थे। बैंक के 410 करोड़ रुपये के निर्गम का मूल्य दायरा 193 से 195 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

कार्वी के लिए प्रावधान में तेजी ला सकते हैं बैंक

कार्वी समूह की इकाइयों में निवेश करने वाले कई बैंक व एनबीएफसी ने अपने वकीलों और कार्वी समूह के अधिकारियों से इस पर चर्चा शुरू कर दी है कि हैदराबाद के इस समूह से रकम की रिकवरी कैसे हो सकती है। इसके अलावा बैंक इस खाते के लिए उस समय प्रावधान में तेजी लाने पर भी विचार कर रहे हैं जब मामला और गंभीर हो जाएगा। अभी बातचीत कार्वी समूह की कंपनियों की तरफ से दी गई जमानत के आसपास केंद्रित है, जिसने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक समेत कई बैंकों से करीब 2,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। एक सूत्र ने कहा, अभी वकीलों के साथ यह पता लगाने के लिए बातचीत हो रही है कि कार्वी की वित्तीय परेशानी की प्रकृति और उसकी गहराई कितनी है। पृष्ठ 2

पुराने नियो विमान बंद करे इंडिगो

डीजीसीए ने इंजन में खामी वाले ए320 नियो विमानों को बदलने का दिया निर्देश

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 25 नवंबर

विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने किफायती विमानन सेवा देने वाली कंपनी इंडिगो को एयरबस ए320 और 321 नियो विमानों का परिचालन बंद करने को कहा है। इन विमानों के टरबाइन ब्लेड टाइटेनियम के बने हैं, जो जल्द खराब होते हैं और उड़ान के दौरान इंजन बंद हो जाता है। नियामक के आज जारी निर्देश के अनुसार विमानन कंपनी इन विमानों की जगह अपने बेड़े में नए विमान शामिल करेगी, जिनका इंजन टरबाइन ब्लेड निकल-क्रोमियम मिश्र धातु का बना होता है।

सूत्रों का कहना है कि नियामक के इस निर्देश से इंडिगो के करीब 50 विमानों के परिचालन पर असर पड़ेगा और कंपनी को अपनी विस्तार योजना को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है।

डीजीसीए ने अपने बयान में कहा, 'इंडिगो अपने मौजूदा बेड़े में जब भी नया ए320 नियो विमान जोड़ेगी तब उसे अपरिवर्तित प्रैट ऐंड व्हिटनी (पीडब्ल्यू) इंजन वाले पुराने ए320 नियो परिवार के एक विमान को परिचालन से बाहर करना होगा। इसके साथ ही नए विमानों का परिचालन बंद हुए विमान के शेड्यूल के हिसाब से करना होगा।'

- नियामक ने कहा कि प्रत्येक नए विमान को शामिल करने पर बेड़े से हटाए पुराने विमान
- नियामक ने पहले 31 जनवरी तय की थी समयसीमा
- इंडिगो के 50 विमानों के परिचालन पर पड़ सकता है असर
- कंपनी ने कहा, फिलहाल परिचालन सारणी में नहीं होगा बदलाव

इंडिगो के बेड़े में अभी 98 ए320 और 321 नियो विमान हैं, जिनमें से 42 विमानों के इंजन ब्लेड को बदला जा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिगो को 120 इंजन से ज्यादा बदलना होंगी। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल इंडिगो विमानों के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, 'इंडिगो इंजनों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रैट ऐंड व्हिटनी और एयरबस के साथ काम कर रही है।'

डीजीसीए ने सोमवार को समीक्षा बैठक की थी जिसमें पाया गया कि नियामक द्वारा तय 31 जनवरी की समययीमा तक इंडिगो इंजनों को बदलने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसके बाद ही डीजीसीए ने यह निर्देश जारी किया है।

डीजीसीए ने 1 नवंबर को इंडिगो को निर्देश दिया था कि वह जनवरी 2020 तक प्रैट ऐंड व्हिटनी इंजनों को संशोधित एलपीटी इंजन से बदल दे।

नियामक ने कहा, 'इंडिगो के प्रयासों से ऐसा नहीं लगता है कि कंपनी समय पर काम पूरा कर पाएगी। इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां 31 जनवरी को हमारे पास ऐसे विमानों का बेड़ा खड़ा हो जाएगा, जिनके इंजन नहीं बदले गए हैं। इससे हमें उनका परिचालन बंद करना होगा, जिससे हवाई यातायात बाधित होगा।' गियर वाले टर्बोफैन के डिजाइन में कई खामियां सामने आई हैं, जिससे विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे आपूर्ति में भी बाधा पहुंची है और मुआवजे के लिए लाखों डॉलर देने पड़े हैं। 2016 में विमान ने ऑयल मेटल डिटेक्टर चेतवानी देनी शुरू की थी। कंपार्टमेंट वाले तीसरे इंजन में एक ऐसा सील था, जिसने अधिक ऊंचाई पर ठीक से काम नहीं किया।

तीसरी समस्या दहन चैंबर लाइनिंग से जुड़ी थी, जिनमें कई हॉट स्पॉट थे, जो लाइनिंग की परिचालन की अवधि घटा रहे थे। इसे दुरुस्त करने के लिए दहन चैंबर लगाया गया। इस साल के शुरू में एक और गंभीर खामी सामने आई। पीऐंडडब्ल्यू ने 2017 के अंत में एक परिवर्तित सील लेकर आई और इसमें शुरू में ही टूट-फूट दिख गई। इस टूटी सील से कम्प्रेशर और टरबाइन को नुकसान पहुंचने लगा। इस वजह से विमानों की उड़ान में मुश्किलें पेश आने लगीं।

बाजार में उछाल, नई ऊंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स

बीएस संवाददाता
मुंबई, 25 नवंबर

सरकार द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के उपायों की घोषणा किए जाने की उम्मीद से बेंचमार्क सूचकांकों में आज शानदार तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही अमेरिका-चीन व्यापार विवाद को लेकर अनुकूल घटनाक्रम से वैश्विक बाजार में आई तेजी का भी घरेलू बाजार को लाभ मिला। बाजार के भागीदारों ने कहा कि शॉर्ट कवरिंग और विदेशी निवेश से बाजार में तेजी आई है।

बेंचमार्क सेंसेक्स 530 अंक चढ़कर 40,889 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक उछलकर 12,074 पर बंद हुआ, जो 3 जून के सर्वकालिक उच्च स्तर से महज 14 अंक नीचे है। चीन द्वारा बौद्धिक संपदा उल्लंघन मामले में पेनल्टी बढ़ाए जाने से अधिकांश वैश्विक बाजार बढ़त पर बंद हुए। चीन के इस कदम से उम्मीद जगी है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ व्यापार विवाद सुलझाने के लिए इच्छुक है।

सेंट्रम ब्रोकिंग के मुख्य कार्याधिकारी संदीप नायक ने कहा, 'अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ा है। दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक बयान से संकेत मिलता है कि इस साल के अंत तक विवाद सुलझ जाएगा। यह स्वागत योग्य घटनाक्रम है।'

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज में शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'संकेत मिले हैं कि अमेरिका और चीन में अगले महीने तजक सुलह हो सकती है जिससे दुनिया भर में निवेशकों का मनोबल सुधरा है।'

बाजार के भागीदारों ने उम्मीद जताई कि विकास को गति देने के उपाय जारी रहेंगे जिससे निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है। कंपनियों की आय बढ़ाने और निवेश में तेजी के लिए सरकार ने 19 सितंबर को कॉरपोरेट कर में कटौती की घोषणा की थी। उसके बाद से सेंसेक्स 13 फीसदी से अधिक चढ़ चुका है। इसके साथ ही दुनिया भर के देशों में मौद्रिक नीति में ढील देने से विदेशी संस्थागत निवेशकों का घरेलू बाजार में निवेश बढ़ा है। विदेशी निवेशकों ने 961 करोड़ रुपये की लिवाली की जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 214 करोड़ रुपये की बिकवाली की। विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी निवेश में तेजी से घरेलू बाजार को बल मिला है। नायक ने कहा, 'अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक रुख में नरमी दिखाने के बाद से विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों को पसंद कर रहे हैं।'

सेंसेक्स में आज येस बैंक और ओएनजीसी को छोड़कर लगभग सभी शेयर बढ़त पर बंद हुए। भारती एयरटेल में 7.2 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। एचडीएफसी 2.6 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ। बीएस के सभी 19 क्षेत्रीय सूचकांक लाभ में बंद हुए।

दलाल पथ पर तेजी

सेंसेक्स की चाल

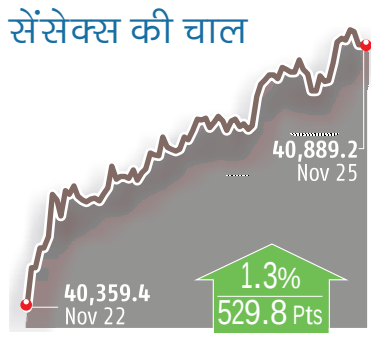

कौन चढ़ें, किसे नुकसान — कीमत रुपये में

	25 नवं.	% बदलाव*
इनमें आई तेजी		
भारती एयरटेल	451.30	7.20
टाटा स्टील	419.55	4.99
इंडसइंड बैंक	1,497.20	3.49
ऐक्सिस बैंक	754.80	3.10
वेदांत	146.05	2.74
इनमें आई गिरावट		
ओएनजीसी	130.90	-2.17
येस बैंक	63.70	-1.70

* पिछले बंद भाव के मुकाबले। स्रोत : कैपिटालाइन

नोकिया के संयंत्र में बनेंगे ऐपल आईफोन

मेघा मनचंदा और टी ई नरसिम्हन
नई दिल्ली, 25 नवंबर

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज कहा कि फिनलैंड की सालकॉम्प नोकिया का चेन्नई संयंत्र करीब 3 करोड़ डॉलर (215 करोड़ रुपये) में खरीदने के लिए तैयार हो गई है। सालकॉम्प ऐपल के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यह संयंत्र करीब छह वर्ष के अंतराल के बाद फिर से चालू होगा। एक कर विवाद के सिलसिले में नोकिया ने यह संयंत्र बंद कर दिया था। कर अधिकारियों के साथ कंपनी के विवाद के बाद संयंत्र 2014 से बंद पड़ा है। सालकॉम्प अगले साल तक परिचालन शुरू कर कसती है और अगले पांच वर्षों में संभवत: 30 करोड़ डॉलर निवेश करेगी।

- सालकॉम्प खरीदेगी नोकिया का चेन्नई संयंत्र
- ऐपल की बड़ी आपूर्तिकर्ता है सालकॉम्प
- इस संयंत्र में अगले साल शुरू हो सकता है उत्पादन
- अगले पांच वर्षों में 30 करोड़ डॉलर से अधिक के निवेश की है योजना

प्रसाद ने कहा कि संयंत्र के पूरी क्षमता से काम शुरू करने के बाद करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक समय था जब यह संयंत्र नोकिया मोबाइल विनिर्माण संयंत्र की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। 2014 में इस संयंत्र के बाद होने के बाद करीब 15,000 लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थीं। इससे पहले एचटीसी, फॉक्सकॉन और एस्सार ने यह संयंत्र बनाने में रुचि दिखाई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया।

नोकिया की विनिर्माण इकाई में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक लोग काम कर रहे थे। हालांकि आयकर विभाग के साथ 210 अरब रुपये का कर विवाद होने के बाद संसंत्र बंद हो गया। इसके बाद फिनलैंड की कंपनी ने नवंबर 2014 में संयंत्र में काम रोक दिया था। नोकिया ने अपना मोबाइल हैंडसेट कारोबार माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। नोकिया का संयंत्र बंद होने के बाद फॉक्सकॉन सहित सभी कंपनियों ने एसईजेड में परिचालन रोक दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर नोकिया का उपकरण एवं सेवा कारोबार अप्रैल 2015 में 7.2 अरब डॉलर में बेच दिया था। हालांकि कर विवाद के बाद संयंत्र को अपनी योजना से अलग करना पड़ा। पिछले साल अप्रैल में नोकिया ने भारत सरकार के साथ कर विवाद 24.14 करोड़ डॉलर का भुगतान कर निपटा लिया था। भारत-फिनलैंड दोहरा कराधान निषेध समझौते के तहत एकबारगी निपटारा हुआ था। अमूमन भारत में कर अधिकारियों का विदेशी कंपनियों के साथ कर संबंधी लंबा खिंचता है। गूगल और वोडाफोन मामला ऐसा ही उदाहरण हैं।

कर अधिकारियों के साथ मामला निपटने के बाद इसकी फैक्टरी सालकॉम्प को बेचने का रास्ता साफ हो गया। सालकॉम्प मोबाइल फोन चार्जर बाजार में दुनिया की अग्रणी कंपनी है। कंपनी की पिछले कई वर्षों से चेन्नई में मौजूदगी रही है। कंपन नोकिया फोन्स को आपूर्ति भी कर रही थी। हालांकि कुछ वर्ष पहले नोकिया का संयंत्र बंद होने के बाद सालकॉम्प ने अपने संयंत्र में उत्पादन जारी रखा और भारत में दो और संयंत्रों में उत्पादन शुरू कर दिया।

प्रदूषण पर अदालत सख्त राज्यों को दिया नोटिस

भाषा
नई दिल्ली, 25 नवंबर

उच्चतम न्यायालय ने वायु की गुणवत्ता, पेयजल और कचरा निष्पादन के मुद्दों पर सोमवार को सभी राज्यों को नोटिस जारी किए। साथ ही केंद्र से कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए 10 दिन के भीतर स्मॉग टावर लगाने के बारे में ठोस निर्णय लिया जाए।

- दिल्ली-एनसीआर में 10 दिन के भीतर स्मॉग टावर लगाने पर निर्णय लेने का दिया निर्देश
- नदियों के प्रदूषण पर अंकुश के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में मांगी रिपोर्ट

शीर्ष अदालत ने प्रदूषण से निबटने के मामले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की और पूछा कि क्यों नहीं आपको प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने पराली जलाने की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसके लिए सरकारी तंत्र ही नहीं बल्कि किसान भी जिम्मेदार हैं। पीठ ने गंगा और यमुना सहित विभिन्न नदियों के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी रिपोर्ट मांगी है।

पराली जलाने पर रोक के बावजूद इसे जलाने का सिलसिला जारी रहने पर अदालत ने पंजाब और हरियाणा को आड़े हाथ लिया। न्यायालय ने कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। पराली जलाने पर अंकुश लगाने में राज्यों के विफल रहने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की और कहा, 'क्या इसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या यह आंतरिक युद्ध से कहीं ज्यादा बदतर नहीं है? बेहतर होगा कि आप इन सभी को विस्फोट से खत्म कर दें।'

शीर्ष अदालत ने दिल्ली में जल और वायु प्रदूषण के मसले पर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए केंद्र और राज्यों को भी फटकार लगाई।

बीएस-4 कारों पर भारी छूट की न करें उम्मीद

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 25 नवंबर

अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन भारत स्टेज (बीएस) 6 उत्सर्जन मानक लागू होने से पहले तगड़ी छूट मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको मायूसी हाथ लग सकती है। वाहन उद्योग के सूत्रों का कहना है कि कीमतों में खास कटौती नहीं की गई है और ग्राहकों के पास चुनने के लिए मॉडल, संस्करण या रंग के अधिक विकल्प भी नहीं रहेंगे।

यात्री वाहनों पर इस महीने भी आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें पिछले महीने के मुकाबले कमी आई है। अलग-अलग मॉडल, पेट्रोल या डीजल इंजन और संस्करण के मुताबिक जो छूट दी जा रही है, वह भी महीने भर से ज्यादा नहीं चलेगी। इसकी वजह यह है कि दीवाली के बाद ज्यादातर डीलरों के पास वाहनों का स्टॉक काफी कम हो गया है।

लैंडमार्क ग्रुप के चेयरमैन संजय ठक्कर कहते हैं, 'विभिन्न ब्रांड के ज्यादातर मॉडलों की पहले ही किल्लत हो गई है। जो लोग बीएस4 मॉडल खरीदना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए।' लैंडमार्क मर्सिडीज, होंडा कार्स, रेनो, निसान, क्राइसलर और फोक्सवैगन की डीलर है। जो तस्वीर बताई जा रही है, वह पिछले साल उत्सर्जन नियमों में बदलाव के वक्त दिखी तस्वीर से एकदम अलग है। आम तौर पर कंपनियां कीमतों में इजाफे से पहले ही उमड़ रही भीड़ का भरपूर फायदा उठाने के लिए आखिरी दिन तक ग्राहकों को लुभाने में जुटी रहती हैं।

महिंद्रा ~25,000 से ~170,000	होंडा कार्स ~45,000 से ~110,000	रेनो ~50,000 से ~300,000
टाटा मोटर्स ~60,000 to ~180,000	टोयोटा ~8,000 to ~150,000	फोक्सवैगन ~57,000 to ~150,000
		फोर्ड ~15,000 to ~50,000

* एक्सचेंज ऑफर/नकद छूट/कॉरपोरेट छूट/फाइनैंस ऑफर आदि

मगर इस बार बीएस-4 इंजन वाले सभी वाहनों के उत्पादन और पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 ही है। इसलिए वाहन कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि इस तारीख तक बीएस-4 वाहनों का उत्पादन बंद हो जाए और उनके पास कोई भी वाहन पंजीकरण के बगैर बचा न रह जाए। हुंडई मोटर इंडिया में प्रमुख (नैशनल सेल्स) विकास जैन कहते हैं,'भविष्य में मांग कैसे पूरी की जाए और स्टॉक भी बिल्कुल बचा न रहे, इसके लिए सटीक अनुमान लगाना होगा।' यही वजह है कि कंपनियां उस तारीख तक सारा स्टॉक निपटा देना चाहती हैं ताकि उन्हें तगड़ी छूट देकर बिक्री नहीं करनी पड़े। फोक्सवैगन इंडिया का ही उदाहरण ले लीजिए। कंपनी ने अपने शोरूमों में खड़ी डीजल कारें बेचने के लिए इसी महीने 'पेट्रोल कार की कीमत में डीजल कार' की योजना शुरू की। मुंबई में कंपनी के एक डीलर ने बताया कि इससे बहुत फायदा हुआ है और ज्यादातर डीजल कारें बिक गई हैं। उसने कहा कि जो और भी अच्छे ऑफर की ताक में बैठे हैं, उन्हें करारा झटका लग सकता है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

व्यापार गोष्ठी

सरकारी कंपनियों का विनिवेश कितना उचित?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या डीजीसीए के निर्देश से इंडिगो के परिचालन पर पड़ेगा असर

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या ग्राहकों के पैसों का दुरुपयोग करने वाले ब्रोकरों पर हो कार्रवाई?	हां	85.71%
	नहीं	14.29%

खबरों में रहे स्टॉक

टाटा स्टील

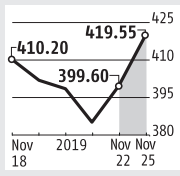

चीन-अमेरिका व्यापार में सुधार की उम्मीद में चढ़े धातु क्षेत्र के शेयर

₹ 399.60 पिछला बंद भाव
₹ 419.55 आज का बंद भाव
▲ 4.99 %

भारती एयरटेल

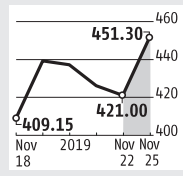

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 421.00 पिछला बंद भाव
₹ 451.30 आज का बंद भाव
▲ 7.20 %

यूनिकेम लैबोरेटरीज

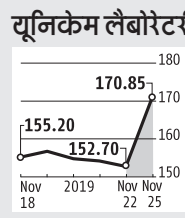

रक्तचाप की दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी

₹ 152.70 पिछला बंद भाव
₹ 170.85 आज का बंद भाव
▲ 11.89 %

अशोका बिल्डकॉन

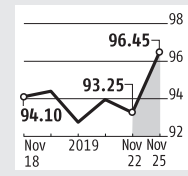

सहायक इकाई को मिली एनएचएआई से 1,000 करोड़ रुपये की परियोजना

₹ 93.25 पिछला बंद भाव
₹ 96.45 आज का बंद भाव
▲ 3.43 %

आईनॉक्स विंड

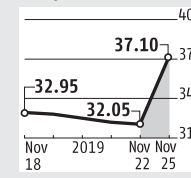

पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिए एसईसीआई से विस्तार

₹ 32.05 पिछला बंद भाव
₹ 37.10 आज का बंद भाव
▲ 15.76 %

संक्षेप में

सेंसेक्स से हटाए जाने की घोषणा से येस बैंक टूटा

येस बैंक का शेयर सोमवार को 4 फीसदी तक टूट गया जब बीएसई ने कहा कि वह इस शेयर को बेंचमार्क सेंसेक्स से बाहर करेगा। वेदांत और टाटा मोटर्स दो अन्य शेयर हैं जिन्हें इंडेक्स से बाहर निकाला जा रहा है। ये शेयर हालांकि बाजार की मजबूत रफ्तार के बीच चढ़ गए क्योंकि सेंसेक्स 1.3 फीसदी चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और नेस्ले इंडिया के शेयर इस आशावाद में चढ़ गए कि सेंसेक्स में शामिल होने के बाद इनमें निवेश प्रवाह देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में होने वाला बदलाव 23 दिसंबर से प्रभावी होगा। *बीएस*

अदाणी ग्रीन एनर्जी के सीएफओ ने दिया इस्तीफा

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने सोमवार को कहा कि उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी अशीष गर्ग ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि गर्ग ने कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद से 25 नवंबर 2015 से इस्तीफा दे दिया। अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है। *भाषा*

गोदरेज एप्लायंसेज की नजर क्षमता विस्तार पर

गोदरेज एप्लायंसेज ने सोमवार को कहा कि अगले दो से तीन साल में वह अपनी सालाना उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 700 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी की योजना 2022 तक विभिन्न सामानों और उपकरणों का उत्पादन 19 लाख इकाई बढ़ाकर 65 लाख इकाई सालाना तक पहुंचाने की है। *भाषा*

कार्वी के लिए प्रावधान कर सकते हैं बैंक

बैंकों, एनबीएफसी ने कार्वी पूछा, पुनर्भुगतान के लिए क्या योजना बना रहा समूह

देव चटर्जी और अनूप रॉय
मुंबई, 25 नवंबर

कार्वी समूह की इकाइयों में निवेश करने वाले कई बैंक व एनबीएफसी ने अपने वकीलों और कार्वी समूह के अधिकारियों से इस पर चर्चा शुरू कर दी है कि हैदराबाद के इस समूह से रकम की वसूली कैसे हो सकती है। इसके अलावा बैंक इस खाते के लिए उस समय प्रावधान में तेजी लाने पर भी विचार कर रहे हैं जब मामला और गंभीर हो जाएगा।

अभी बातचीत कार्वी समूह की कंपनियों की तरफ से दी गई जमानत के आसपास केंद्रित है, जिसने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक समेत कई बैंकों से करीब 2,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। एक सूत्र ने कहा, अभी वकीलों के साथ यह पता लगाने के लिए बातचीत हो रही है कि कार्वी की वित्तीय परेशानी की प्रकृति और उसकी गहराई कितनी है। एक बैंकर ने कहा, हम कार्वी से यह जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारी रकम वापस करने के लिए वह क्या कदम उठा रही है।

बैंकिंग सूत्रों ने कहा कि कार्वी ने अभी तक भुगतान में चूक नहीं की है और प्रबंधन ने आश्वस्त किया है कि समूह के पास पर्याप्त रकम है और भुगतान में किसी तरह की चूक नहीं होगी। लेकिन बैंक कोई जोखिम लेना नहीं चाहता और वह इस खाते पर प्रावधान में इजाफा कर सकता है और वह भी सबसे अच्छे नियम के आधार पर। यह जानकारी निजी बैंक के एक वरिष्ठ बैंकर ने दी, जिनका कार्वी में निवेश है।

बैकर ने कहा, कुछ कर्ज पर्याप्त जमानत के साथ सुरक्षित है और इस पर चिंता की बात नहीं है। एक बैंकर ने कहा, सामान्य स्थिति में हमने प्रावधान के बारे में शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन आरबीआई के अंकेक्षकों की राय अलग हो सकती है। अगर किसी एक बैंक के साथ कार्वी भुगतान में चूक करती है तो सभी बैंकों को इसे एनपीए के तौर पर दिखाना होगा। बेसल के नियमों में इस पर काफी कुछ है और बैंक अब बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेते।

कार्वी की बढ़ती पूंजीगत जरूरतों को देखते हुए बैंक कार्वी के प्रोफाइल में कमजोरी से भी चिंतित हैं, जो मुख्य रूप से रिसीवेबल्स में देरी के अलावा फंड जुटाने में देरी के कारण है। क्रिसिल ने सोमवार को कहा था, मुख्य रूप से प्राप्तियों (रिसिवेबल) के अलावा रकम जुटाने में देरी के कारण कार्यशील पूंजी की बढ़ती दरकार से प्रोफाइल कमजोर हुआ है। खास तौर से आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्तियों में देरी और सहायक कंपनियों के कॉन्ट्रेक्ट सेंटर बिजनेस के बड़े ग्राहक से प्राप्तियों में देरी का समूह की नकदी पर असर पड़ेगा।

शुक्रवार को सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को स्टॉक ब्रोकिंग के लिए नए क्लाइंट शामिल करने से रोक दिया था और यह रोक क्लाइंट की प्रतिभूतियों के कथित दुरुपयोग पर लगाई गई। सेबी ने अपने आदेश में कहा था, प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कार्वी ब्रोकिंग ने शुद्ध रूप से 1,096 करोड़ रुपये समूह की कंपनियों कार्वी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2019 के बीच हस्तांतरित किए।

इसके अलावा सेबी ने कहा है, कार्वी ने डीपी खाते में प्रतिभूतियां न होते हुए भी 31 मई 2019 तक नौ क्लाइंटों के खाते से 485 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां बेच दी। साथ ही इन क्लाइंटों में से छह के खाते से 162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिभूतियां हस्तांतरित की।

सेबी ने पाया कि चार क्लाइंटों की 257 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां गिरवी रख दी गई और यह काम 1 जून 2019 से 22 अगस्त 2019 के बीच हुआ। साथ ही ऐसे चार क्लाइंटों की 217 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां कार्वी ने रिकवर की। आईसीआईसीआई बैंक के आधिकारिक प्रवक्ता ने क्लाइंट से संबंधित पूछताछ पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। इस बैंक का कार्वी समूह की सभी इकाइयों में सबसे ज्यादा निवेश है और यह 875 करोड़ रुपये है। लेकिन एक आंतरिक सूत्र ने कहा कि यह 600 करोड़ रुपये है।

आदित्य बिड़ला फाइनैंस का कार्वी में निवेश 109 करोड़ रुपये है। उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त जमानत है। आदित्य बिड़ला फाइनैंस के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।

कार्वी का संकट, लेनदार परेशान

- लेनदारों को कमजोर वित्तीय प्रोफाइल कर रहा है चिंतित
- क्रिसिल ने कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज एनसीडी को किया डाउनग्रेड
- कार्वी की इकाइयों में बैंकों का निवेश 2,900 करोड़ रुपये है
- अभी तक बैंकों ने कार्वी की तरफ से किसी डिफॉल्ट की जानकारी नहीं दी है

कुल बकाया 40 करोड़ रुपये से भी कम : कार्वी

समी मोडक
मुंबई, 25 नवंबर

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग (केएसबीएल) पर उसके क्लाइंटों का बकाया 40 करोड़ रुपये से भी कम है और इसका भुगतान जल्द किया जाएगा। कंपनी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ब्रोकरेज ने इस दावे का खंडन किया है कि उसने 2,000 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की है।

ब्रोकरेज फर्म के आला अधिकारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि 2,000 करोड़ रुपये के आंकड़े कहां से आए। मैं कहना चाहता हूं कि सभी प्रतिभूतियां बरकरार हैं। ये सभी रेग्युलर अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ऐसे में निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनकी प्रतिभूतियों का क्या होगा। विशेष तौर पर इस मामले में किसी तरह की चूक नहीं हुई है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि प्रतिभूतियों के साथ सही तरीके व्यवहार नहीं हुआ। उनका इस्तेमाल अन्य मकसदों के लिए हुआ। अधिकारी ने सेबी के आदेश पर कुछ नहीं कहा क्योंकि मामला विचाराधीन है। शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी ने क्लाइंट के फंडों का दुरुपयोग करने पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करते हुए उसे नए क्लाइंट जोड़ने से रोक दिया था। अधिकारी ने कहा कि कुछ क्लाइंटों के शेयरों का इस्तेमाल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए हुआ। अधिकारी ने कहा, हम एक एक्सचेंज पर बेचकर दूसरे एक्सचेंज पर खरीद लेते हैं। मूल रूप से यह आर्बिट्रेज है। ये चीजें सही तरीके से नहीं समझी गई। इस बारे में हम जल्द ही नियामक के सामने अपना पक्ष रखेंगे। आंकड़े बड़े दिख रहे हैं क्योंकि यह बड़ी अवधि का है। रोजाना आधार पर यह काफी छोटा है। क्लाइंटों के 40-50 करोड़ रुपये चुकाने की दरकार होगी, जो जल्द कर दिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि सेबी के आदेश के हमारे क्लाइंटों की चिंता शुरू हो गई और कंपनी वास्तविकता बताने के लिए उनसे संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा, हम हर किसी को बता रहे हैं कि सबकुछ ठीक होगा। चूंकि हम हर चीजों पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं लिहाजा हम उनका भरोसा दोबारा हासिल कर लेंगे और चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएगी।

अवमानना मामले में ऐक्सिस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रमुख तलब

सुब्रत पांडा
मुंबई, 25 नवंबर

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सोमवार को ऐक्सिस बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रमुखों को नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन करने के खिलाफ अवमानना कार्यवाही में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा गया है।

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि अगर बैंक के मुख्य कार्याधिकारी इस मामले में उपस्थित होने में नाकाम रहते हैं तो वह अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं जिनमें उनके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी करना शामिल है क्योंकि कंपनी मामलों के मंत्रालय की तरफ से बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बैंकर उपस्थित होने में नाकाम रहे। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। अमिताभ चौधरी ऐक्सिस बैंक के सीईओ हैं जबकि जरीन दारूवाला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रमुख हैं।

ऐक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि एनसीएलटी का आदेश मिलने के बाद बैंक उचित कदम उठाएगा। इस साल अप्रैल में एनसीएलटी के मुंबई पीठ ने ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन करने पर अमिताभ चौधरी, जरीन दारूवाला, रमेश बावा और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया था। उनके खिलाफ दाखिल अवमानना मामले में ट्रिब्यूनल ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था।

दिसंबर 2018 में एनसीएलटी ने आदेश पारित किया था, जिसमें आईएलऐंडएफएस के नौ निदेशकों को अपनी परिसंपत्तियां बेचने और अपनी परिसंपत्तियों का अधिकार तीसरे पक्षकार को देने से रोक दिया था।

बाद में 16 जनवरी 2019 को एनसीएलएटी ने उन्हें किसी एक बैंक खाते से 2 लाख रुपये मासिक निकासी की अनुमति दी थी।

बीएस-4 कारों पर तगड़ी छूट की न रखें उम्मीद

पृष्ठ 1 का शेष...

अर्थव्यवस्था में सुस्ती और उत्सर्जन नियमों में बदलाव के कारण होने वाली दिक्कत को भांपकर कंपनियां कोई कसर नहीं छोड़ रहीं। हुंडई के जैन कहते हैं, 'हम त्योहारों पर शुरू किए ऑफर अब भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले महीने से कुछ ऑफर खत्म कर दिए गए हैं।' उन्होंने कहा कि अक्टूबर वाला जोश अब तक दिख रहा है। जैन ने बताया कि अभी कंपनी की नियॉस और इलांत्रा कारों में ही बीएस-6 इंजन है, लेकिन बाकी कारों में भी फरवरी तक बीएस-6 इंजन आ जाएंगे। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया के लिए हालात उतने चुनौती भरे नहीं हैं। कंपनी बीएस-6 इंजन लाने में सबसे आगे रही है और अप्रैल से अब तक बीएस-6 इंजन वाली 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच चुकी है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक (सेल्स ऐंड मार्केटिंग) शशांक श्रीवास्तव कहते हैं, 'बीएस-6 कारों की काफी मांग है। बीएस-4 कारों पर छूट अब भी है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले कम है। अलग-अलग मॉडलों पर अब पहले के मुकाबले 4-5 हजार रुपये कम छूट मिल रही है।'

बीएस बातचीत

नरमी ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का समय

पैकेटबंद फूड कंपनी नेस्ले इंडिया ने जुलाई से सितंबर की अवधि में दमदार वित्तीय नतीजे के साथ उपभोक्ता वस्तु कंपनियों के बीच उमदा प्रदर्शन किया है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक **सुरेश नारायणन** ने **विवेट सुजन पिंटो** से बातचीत में कंपनी की रणनीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। पेश हैं मुख्य अंश:

बाजार में नरमी के बावजूद आप कैसे दमदार प्रदर्शन करने में सफल रहे? क्या आप नए उत्पादों को लॉन्च करना जारी रखेंगे?

हमारे प्रमुख ब्रांडों का दमदार प्रदर्शन जारी रहेगा। मूल्य और बिक्री में वृद्धि के मोर्चे पर मैगी अब 2015 के संकट से पहले की स्थिति में आ चुकी है। हम अपनी अन्य श्रेणियों में भी लगभग यही प्रवृत्ति देख रहे हैं। इसकी मुख्य वजह हमारी पहुंच आधारित बिक्री में वृद्धि की रणनीति है। हम अपने पोर्टफोलियो में तमाम उपभोक्ताओं को जोड़ रहे हैं। बेहतर कीमत-मूल्य समीकरण, नवाचार एवं नवीकरण पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के अलावा उत्पादों को बाजार में उतारने में तत्परता के कारण ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिली है।

मैगी संकट से पहले हम सालाना दो उत्पादों को बाजार में उतारते थे। लेकिन अब हम हर महीने दो उत्पादों को लॉन्च कर रहे हैं। इससे हमें बिक्री में 4 फीसदी की वृद्धि दर्ज करने में मदद मिली है। साथ ही हम अपने ब्रांड में निवेश करने, मीडिया के जरिये ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और क्लस्टर आधारित वितरण मॉडल को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन सब से हमें मंदी के बावजूद अच्छी वृद्धि दर्ज करने में मदद मिली। हमें इस रणनीति में बदलाव करने का फिलहाल कोई कारण नहीं दिखता।

बिस्कुट जैसी बुनियादी श्रेणी में कोई खास वृद्धि नहीं दिख रही है जबकि प्रसंस्कृत खाद्य जैसी श्रेणी में नेस्ले अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसा कैसे संभव हुआ?

एक निश्चित स्तर पर ग्राहक खुद अपना दिमाग लगाते हैं कि उन्हें खपत के लिए किन उत्पादों को खरीदना है। उनकी सूची में खानेपीने की चीजें होती हैं लेकिन वे उनकी मात्रा खुद निर्धारित करते हैं। ठीक उसी समय उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले उन उत्पादों को पूरी तरह नहीं छोड़ते जो उन्हें जीवन का बेहतर अनुभाव प्रदान करते हैं। नेस्ले का पोर्टफोलियो उसी के अनुरूप है। उपभोक्ताओं की राह बदल रही है और हमारी रणनीति उसमें भागीदारी करने और उन उत्पादों को लगातार उतारने की होगी जो लोगों को जीवनशैली बेहतर करने में मदद कर सके। खपत में नरमी वास्तव में मेलजोल बढ़ाने का एक अवसर है।

आप ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में वितरण बढ़ा रहे हैं जबकि ग्रामीण बाजार में मंदी के कारण अन्य उपभोक्ता वस्तु कंपनियां शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ऐसा क्यों?

हमारी कुल बिक्री में ग्रामीण बाजार का योगदान 20 से 25 फीसदी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य कंपनियों को होने वाली बिक्री के मुकाबले काफी कम है क्योंकि उनकी कुल बिक्री में ग्रामीण बाजार का योगदान 35 से 40 फीसदी है। यह कहना गलत होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई खपत नहीं है। हां, ग्रामीण बाजार को झटका लगा है और शहरों के मुकाबले ग्रामीण बाजार में वृद्धि कमजोर है। हालांकि ग्रामीण एवं कस्बाई बाजारों का प्रदर्शन हमारे लिए अच्छा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास शहरी उपभोक्ताओं की तरह क्रय शक्ति नहीं होती लेकिन बेहतर जीवन के लिए उनकी भी आकांक्षा है।

एफपीआई निवेश 6 अरब डॉलर

कर सुधार व वैश्विक तरलता के कारण दो महीने में एफपीआई निवेश बढ़ा

समी मोडक
मुंबई, 25 नवंबर

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार में अप्रत्याशित रफ्तार से निवेश कर रहे हैं। इक्विटी (नकदी) में उनका शुद्ध निवेश पिछले दो महीने में 6 अरब डॉलर यानी 44,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। देसी बाजार में दो महीने में एफपीआई का निवेश मई के बाद का सर्वोच्च स्तर है। एफपीआई के तेज निवेश ने बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी को दो महीने में 13 फीसदी चढ़ने में मदद की है।

सरकार की तरफ से सितंबर में कंपनी कर में की गई कटौती, वैश्विक स्तर पर सहज मौद्रिक नीति आदि को देसी इक्विटी में एफपीआई के तेज निवेश की वजह मानी जा रही है। कार्की ने कहा, वैश्विक नकदी में सुधार यूरोपीय सेंट्रल बैंक की तरफ से नवंबर से 22 अरब डॉलर प्रति माह की नकदी सहजता और अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से बॉन्ड खरीद कार्यक्रम बढ़ाकर 60 अरब डॉलर मासिक करने की वजह से हुआ है।

इक्विटी बाजार के निवेशकों के लिए सकारात्मक खबर यह हो सकती है कि वैश्विक अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि वैश्विक केंद्रीय बैंक अगले साल भी बेहतर रुख जारी रहने रखेंगे।

मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में कहा, फेड ने अपना कदम बढ़ा दिया है, लेकिन हमारा अनुमान है कि वैश्विक मौद्रिक नीति आगे और सहज होगी।

एफपीआई निवेश से बेंचमार्क सूचकांक को 13 फीसदी चढ़ने में मदद मिली है

पिछले दो महीने में हुए 6 अरब डॉलर के निवेश विशिष्ट कंपनियों में निवेश के कारण है, जहां निवेशकों की तरफ से बड़ी शेयर बिक्री की है। उदाहरण के लिए गुरुवार को हुए 70 करोड़ डॉलर के निवेश का बड़ा हिस्सा ज़ी एंटरटेनमेंट का शेयर उनके प्रवर्तकों से खरीदने पर निवेशित हुआ। इसी तरह एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ की शेयर बिक्री ने भी बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद की।

एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को लेकर एफपीआई की प्राथमिकता ने भी बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचने में मदद की। सोमवार को बेंचमार्क सेंसेक्स 40,889 अंकों की नई ऊंचाई पर बंद हुआ और निफ्टी 12,074 पर, जो पिछली रिकॉर्ड ऊंचाई से महज 14 अंक नीचे है।

डीएचएफएल व 5 फर्मों की होगी एसएफआईओ जांच

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 25 नवंबर

सरकार ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस कंपनी (डीएचएफएल) और पांच अन्य रियल एस्टेट कंपनियों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से कराने के आदेश दिए हैं। कंपनी मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

एसएफआईओ जिन पांच कंपनियों की जांच करेगा उनमें इमिडिएट रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, टेनासिटी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजेन स्काईक्रेपर शामिल हैं।

कंपनी मामलों के मंत्रालय को 24 अक्टूबर 2019 को क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) की तरफ से डीएचएफएल की जांच रिपोर्ट

मिली थी। ठाकुर ने कहा, डीएचएफएल और पांच अन्य कंपनियों की जांच का काम 6 नवंबर 2019 को एसएफआईओ को सौंप दिया गया और जांच पूरी करने के समय के बारे में अभी संकेत नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय निदेशक की रिपोर्ट में बैंकों व अधिकारियों की मिलीभगत का जिक्र नहीं है। इस रिपोर्ट में हाउसिंग फाइनैंस कंपनी की तरफ से लिए गए 95,615 करोड़ रुपये के कर्ज का ब्योरा है, जो 31 मार्च 2019 को बकाया कर्ज पर आधारित है।

डीएचएफएल ने टाल दी तिमाही नतीजे की घोषणा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 25 नवंबर

मुश्किल में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने आज होने वाली निदेशक मंडल की बैठक टाल दी, जहां दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे को मंजूरी दी जानी थी क्योंकि आरबीआई की तरफ से नियुक्त प्रशासक को कंपनी के वित्तीय नतीजे को अंतिम रूप देने के लिए सांविधिक अंकेक्षकों के साथ विस्तृत चर्चा की दरकार है। एक्सचेंज को भेजी सूचना में डीएचएफएल ने कहा कि संशोधित तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी।

कंपनी परिचालन व भुगतान में चूक के कारण आरबीआई ने हाल में डीएचएफएल के निदेशक मंडल पर नियंत्रण हासिल किया है और आर सुब्रमण्याकुमार को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है। इसके अलावा आरबीआई ने प्रशासक की मदद के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की है। सलाहकार समिति में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन राजीव लाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक व सीईओ एन एस कन्नन और एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी एन एस वेंकटेश शामिल हैं।

डीएचएफएल ने नियामकीय सूचना में कहा, प्रशासक और सलाहकार समिति को कामकाज का तरीका तय करने के लिए कुछ वक्त की दरकार होगी।

आरबीआई जल्द ही वित्तीय सेवा प्रदाता की दिवालिया प्रक्रिया आदि के तहत कंपनी के समाधान की प्रक्रिया शुरू करेगा। बैंकिंग नियामक प्रशासक को इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी से भी संपर्क करेगा। पहली तिमाही में डीएचएफएल का शुद्ध नुकसान 242.48 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले की समान अवधि में उसे 431.71 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की कुल आय पहली तिमाही में पिछले साल की समान अवधि के 3,154.25 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,399.84 करोड़ ररुपये रही। कंपनी एक साल से ज्यादा वक्त से नकदी की समस्या से जूझ रही है।

एनबीएफसी की दिवालिया प्रक्रिया बैंकों के लिए सकारात्मक

गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों (एनबीएफसी, एचएफसी) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू किए जाने की अनुमति दिया जाना बैंकों के लिए सकारात्मक कदम है। इस कदम से इन वित्तीय कंपनियों में फंसे कर्ज का सुनियोजित तरीके से समाधान हो सकेगा। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा, एनबीएफसी को दिवाला कानून के तहत लाए जाने का कदम बैंकों के लिए सकारात्मक होगा। दिवाला संहिता में दबाव में फंसी कंपनियों सुनियोजित तरीके से समाधान प्रावधान है।

सरकार ने
यह अधि

डिजिटल कर : भारत के मसलों पर आम राय नहीं

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 25 नवंबर

डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने को लेकर भारत की ओर से उठाए गए मुद्दों पर कोई आमराय नहीं बन पाई है। गूगल, नेटफ्लिक्स, एमेजॉन, फेसबुक और उबर आदि कंपनियों पर नए डिजिटल कर का प्रारूप तय करने को लेकर तय की गई अंतिम समय सीमा आगे बढ़ सकती है। इस चर्चा में शामिल देशों ने इस समय सीमा को जनवरी तय की थी।

पिछले हफ्ते पेरिस में हुई बैठक में तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे जिनका समाधान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की ओर से जारी किए गए मसौदा पत्र में नहीं दिया गया है। इस संगठन में भारत सहित कुल 134 देश शामिल हैं। 9 अक्टूबर को जारी अपने 21 पृष्ठीय मसौदा पत्र में ओईसीडी ने तीन अलग अलग कर फार्मूला दिए हैं, जिन पर जनता की राय मांगी गई है।

बैठक के दौरान भारत ने कुछ मुद्दे उठाए थे जिनमें व्यापार का दायरा क्या हो जिसके आधार पर कर वसूला जाएगा, वैश्विक स्तर पर और उनके अधिकार क्षेत्र में सृजित होने वाले राजस्व की शुरुआती सीमा और किसी स्थायी प्रतिष्ठान के अभाव में आभासी कंपनी के विचार के आधार पर किस तरह से कड़ी (नेक्सस) तैयार होगी, जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इनके अलावा भारत ने डिजिटल फर्मों के विपणन से जुड़ी अमूर्त संपत्ति से अर्जित डीम्ड अतिरिक्त लाभ या गैर नियमित आय को लेकर भी चर्चा की थी। कारोबार के दायरे को लेकर विकसित देश भारत और अन्य विकासशील देशों से चाहते हैं कि वे केवल उपभोक्ता से संबंधित कारोबार पर ही कर लें जिसमें सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को सेवा मुहैया कराई जाती है और उन्हें बिजनेस टू बीजनेस बिक्री मसलन औद्योगिक सामान और पेशेवर सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियों को कर से बाहर रखना चाहिए।

हालांकि, भारत पूरे कारोबार की बजाय केवल एक खंड पर कर लगाने के पक्ष में नहीं है। पेरिस में हुई कार्यबल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अधिकारी ने कहा, 'हमने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल कंपनियां बी2बी और बी2सी दोनों में हैं। केवल एक खंड को कवर करने से पूरा दायर सिमट जाएगा साथ ही इस तरह से राजस्व में उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी।'

ओईसीडी के प्रस्ताव में उच्च डिजिटल कारोबारी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संभावित कार्व-आउट पर भी विचार किया जाएगा विशेष तौर पर इसके लिए शोधन उद्योगों या वित्तीय सेवाओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आकार की सीमाओं जैसे कि 75 करोड़ यूरो का शुरुआती राजस्व पर भी विचार किया जा सकता है।

भारत की ओर से उठाया गया दूसरा मसला था कि नए स्टैंडएलोन नियम के तहत अतिरिक्त आय पर आवंटित कराधान अधिकर और ऐसे में वैकल्पिक शुरुआती सीमा का निर्धारण। ऐसा भारत में एक वर्चुअल कंपनी खड़ी कर किया जा सकता है जिस पर इस बात का असर नहीं होगा कि कारोबार का उनके क्षेत्राधिकार में ऐसी कर योग्य उपस्थिति है अथवा नहीं जो मौजूदा नेक्सस की शुरुआती सीमा को पूरा करे।

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कर कानूनों के तहत नेक्सस से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका एक निश्चित क्षेत्राधिकार के साथ पर्याप्त आर्थिक संबंध हैं जिसके लिए वह क्षेत्राधिकार उस विशेष कंपनी पर कर लगाने में समर्थ हो।

इसे लागू करने के लिए भारत ने वर्चुअल उपस्थिति को परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें उन कंपनियों को शामिल किए जाए जिसका उस संबंधित देश में कोई भौतिक प्रतिष्ठान नहीं हो।

इसके अलावा भारत ने अतिरिक्त लाभों के वितरण पर भी चर्चा की है जिसके तहत उपयोगकर्ताओं, प्रत्येक देश के उपयोगकर्ताओं और वस्तु की संबंधित मांग के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।

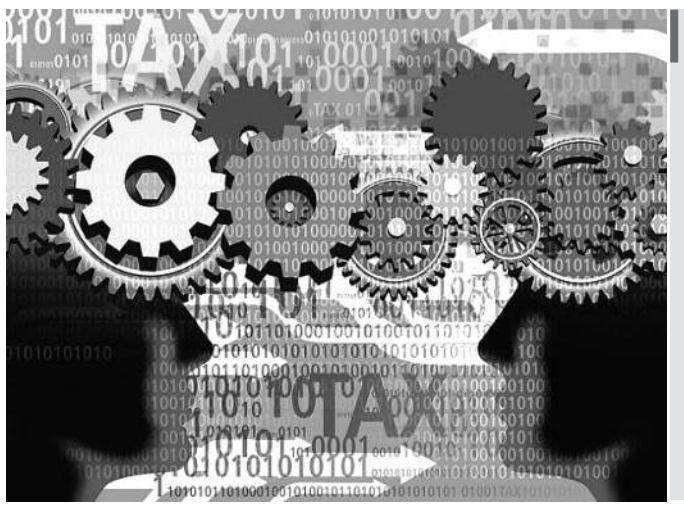

ओईसीडी का मसौदा

- गूगल, नेटफ्लिक्स, एमेजॉन, फेसबुक उबर आदि कंपनियों पर नए डिजिटल कर का प्रारूप तय करने की बढ़ सकती है समय सीमा
- 21 पृष्ठ के मसौदा पत्र में ओईसीडी ने तीन अलग अलग कर फार्मूला दिया
- इस संगठन में भारत सहित कुल 134 देश शामिल
- पिछले हफ्ते पेरिस में हुई बैठक, 90 देशों ने लिया था हिस्सा

महज 60 प्रतिशत मकानों में रसोई गैस का इस्तेमाल

शाइन जैकब और सोमेश झा
नई दिल्ली, 25 नवंबर

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत के कुल परिवारों में से करीब 61 प्रतिशत रसोई गैस (एलपीजी) का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल सरकार ने दावा किया था कि दिसंबर 2018 तक करीब 90 प्रतिशत परिवारों तक रसोई गैस पहुंच गई है।

एनएसओ की ओर से शनिवार को जारी 76वें दौर के सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 48.3 प्रतिशत परिवार, जबकि शहरों में 86.6 प्रतिशत लोग रसोई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सर्वे जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच कराया गया था। एनएसओ के सर्वे में पहली बार रसोई गैस कनेक्शन को शामिल किया गया है, इसलिए तुलना करने के लिए पिछले सर्वे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए एनएसओ ने देश के 1,00,000 से ज्यादा परिवारों से उनके ईंधन के प्राथमिक स्रोत के बारे में आंकड़े जुटाए हैं।

दिलचस्प है कि गांवों में अभी भी 44.5 प्रतिशत परिवार लकड़ी, फसल के अवशेष, चिपरी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में करते हैं, वहीं 2018 में शहरों में इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 5.6 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने इस साल अक्टूबर में दावा किया था कि रसोई गैस 96.5 प्रतिशत परिवार में पहुंच गई है। सरकार ने इसे अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की सफलता के रूप में पेश किया था। पेट्रोलियम प्लानिंग ऐंड एनलिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2018 तक देश में 89.5 प्रतिशत घरों में रसोई गैस पहुंच गई है। रसोई गैस का कम इस्तेमाल करने वाले राज्यों में ओडिशा (32.6 प्रतिशत), झारखंड (32.9 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (42.8 प्रतिशत) राजस्थान (48.1 प्रतिशत) मध्य प्रदेश (48.3 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (50.2 प्रतिशत) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2016 में शुरू की गई पीएमयूवाई पर बहुत ज्यादा जोर दिए जाने के बावजूद महज 11 प्रतिशत परिवारों को सर्वे के काल से पिछले 3 साल के दौरान रसोई गैस से जुड़ा सरकारी लाभ मिला है। सर्वे में कहा गया है कि करीब 13 प्रतिशत मकानों को रसोई गैस कनेक्शन से जुड़ा सरकारी लाभ कभी न कभी मिला है। इसमें से 88 प्रतिशत (करीब 11 प्रतिशत) को रसोई गैस योजना का लाभ पिछले 3 साल में मिला है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विकास रावल ने कहा, 'एनएसओ के आंकड़े में देश में रसोई गैस का इस्तेमाल करने वालों की संख्या है और सरकार का दावा रसोई गैस कनेक्शन को लेकर उज्ज्वला योजना की सफलता को लेकर है। इसकी संभावना ज्यादा है कि बहुत से लोगों ने उज्ज्वला योजना का लाभ लिया हो और वे वित्तीय समस्या की वजह से उसके बाद गैस भराने में सफल न रहे हों और इसकी वजह से वे रसोई गैस का इस्तेमाल न कर रहे हों।' एनएसओ के सर्वे में कहा गया है कि रसोई गैस का इस्तेमाल कम होने की एक बड़ी वजह इसके बढ़े दाम हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि पीएमयूवाई से सिलेंडर लेने वाले करीब 87 प्रतिशत ग्राहक कम से कम दूसरी बार गैस भराने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के लाभार्थियों को विकल्प दिया गया है कि 14.2 किलो की जगह पर अपनी जरूरत के मुताबिक 5 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं। तेल विपणन कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहुंच की परिभाषा को लेकर बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा, 'समस्या पहुंच की परिभाषा को लेकर हो सकती है। तेल कंपनियों के मार्केटिंग नेटवर्क की पहुंच 96.5 प्रतिशत परिवारों तक हो गई है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिन लोगों तक रसोई गैस पहुंच गई है, वे इसका इस्तेमाल भी करते हों।'

एक अन्य सूत्र ने कहा कि सर्वे में प्राथमिक ईंधन का मसला भी हो सकता है। उन्होंने कहा, 'संभव है कि तमाम परिवारों के पास रसोई गैस सिलेंडर हो, लेकिन उन्होंने लकड़ी को इस्तेमाल होने वाला प्राथमिक ईंधन बताया हो।'

तीन तेल विपणन कंपनियों के अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) के कुल मिलाकर 27.36 करोड़ सक्रिय रसोई गैस उपभोक्ता हैं, जिनके कुल 24,127 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यह पहला मौका है जब सरकार की योजनाओं का लाभ परिवारों तक पहुंचने को लेकर सर्वे कराया गया है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य ध्यान यह अनुमान लगाना नहीं था कि सरकार की योजनाओं से कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है।

आंकड़ों में भारी अंतर

- सरकार ने दावा किया था कि देश भर के 95 प्रतिशत घरों में रसोई गैस पहुंच गई है, लेकिन एनएसओ के आंकड़े सरकार के दावों के विपरीत
- सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 48.3 प्रतिशत जबकि शहरों में 86.6 प्रतिशत परिवार रसोई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं
- विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा संभव है कि परिवारों ने रसोई गैस कनेक्शन लिए हों, लेकिन वे अब भी खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हों

साबरमती रिवरफ्रंट की जमीन बिक्री में मदद करेगी जेएलएल

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 25 नवंबर

अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट की जमीन के मुद्रीकरण के लिए प्रमुख रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म जेएलएल इंडिया के साथ समझौता हुआ है। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के अधीन बनी विशेष उद्देश्य इकाई साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआरएफडीसीएल) ने 200 हेक्टेयर की रिवरफ्रंट परियोजना की करीब 15 लाख वर्गफुट जमीन के मुद्रीकरण के लिए जेएलएल इंडिया के साथ समझौता किया है।

जेएलएल ने कहा है कि अनुमान के मुताबिक इस जमीन की कुल कीमत करीब 3,500 करोड़ रुपये होगी। एसआरएफडीसीएल के इस भूखंड के मुद्रीकरण में एंड टु एंड कंसल्टिंग और पूरे लेन देन का प्रबंधन का काम शामिल है।

भूखंड के मुद्रीकरण में एसआरएफडीसीएल की मदद के लिए जेएलएल की रणनीतिक सलाहकार और लेन देन सलाहकार टीमें लगेंगी। इसमें रियल एस्टेट बाजार का अध्ययन और सर्वे, विपणन, कीमत तय करने, ब्रांडिंग और रणनीति तैयार करने व लेन देन की सलाह देने का काम शामिल होगा। जेएलएल की टीम बाजार का अध्ययन करेगी, जिसेस इस जमीन को खरीदने वालों और किरायेदारों का मिला जुला और बेहतर विकल्प मिल सके।

जेएलएल इंडिया के सीईओ और कंट्री हेड रमेश नैयर ने कहा, 'एसआरएफडीसीएल से जेएलएल को ठेका मिलने से कंपनी का देश के लेन देन में प्रभुत्व का पता चलता है और यह साबित करता है कि हम इस कारोबार में श्रेष्ठ हैं।'

- साबरमती रिवरफ्रंट की जमीन के मुद्रीकरण के लिए प्रमुख रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म जेएलएल से समझौता
- 200 हेक्टेयर की रिवरफ्रंट परियोजना की करीब 15 लाख वर्गफुट जमीन के मुद्रीकरण की योजना
- अनुमान के मुताबिक इस जमीन की कुल कीमत करीब 3,500 करोड़ रुपये

स्पेक्ट्रम नीलामी पर अगले माह विचार

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 25 नवंबर

दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रस्ताव पर चर्चा डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन (डीसीसी) की अगली बैठक में हो सकती है। दिसंबर में डीसीसी की बैठक प्रस्तावित है। डीसीसी दूरसंचार पर फैसले करने वाली केंद्र सरकार की शीर्ष इकाई है।

प्रकाश ने संवाददाताओं से कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी का प्रस्ताव आयोग के समक्ष मंजूरी के लिए उसकी अगली बैठक में आने की उम्मीद है, जो दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में होने वाली है। उन्होंने बैठक की तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

उम्मीद की जा रही है कि दूरसंचार समिति भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सुझावों को मंजूरी देगी, जिसमें 5जी स्पेक्ट्रम की मात्रा व मूल्य और प्रीमियम 700 मेगाहट्र्ज बैंड एयरवेव्स के बारे में सिफारिशें की गई हैं।

अगस्त 2018 की सिफारिशों में नियामक ने स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य को लेकर अपनी राय पेश की थी। वहीं सलाह प्रक्रिया के दौरान इस क्षेत्र के हिस्सेदारों के एक वर्ग ने चिंता जताई थी। तीन दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम के मूल्य को लेकर चिंता जताई थी और सरकार से अनुरोध किया था कि कीमतें कम की जानी चाहिए। इसके बाद यह मामला नियामक के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया था।

ट्राई ने जुलाई 2019 में अपनी मूल सिफारिशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि 5जी में टेलीकॉम सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली रेडियोवेव्स और अन्य बैंड की नीलामी 5.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की शुरुआती कीमत से होनी चाहिए।

स्पेक्ट्रम की अंतिम नीलामी 26 अक्टूबर 2016 को हुई थी, जिसमें सिर्फ 40 प्रतिशत स्पेक्ट्रम की पेशकश बिक्री के लिए की गई थी। उस नीलामी में सरार ने सिर्फ 965 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री से 65,789 करोड़ रुपये जुटाए थे। कुल 2,354.44 मेगाहट्र्ज की पेशकश 5.63 लाख करोड़ रुपये आधार मूल्य पर की गई थी।

जिस बैंडविथ की बिक्री नहीं हुई है, उसमें कीमती 700 मेगाहट्र्ज शामिल है। ज्यादा आधार मूल्य की वजह से दूरसंचार कंपनियां इसे नहीं ले पाईं। इस बैंड को प्रीमियम माना जाता है क्योंकि इसकी इंडोर में बेहतर पहुंच है। ट्राई ने सिफारिश की है कि इसका आधार मूल्य प्रति मेगाहट्र्ज मूल्य 6,568 करोड़ रुपये होना चाहिए, जो 2016 में हुई प्रति मेगाहट्र्ज 11,485 करोड़ रुपये की तुलना में 43 प्रतिशत कम है।

सरकार ने 2017-18 और 2018-19 वित्त वर्ष में स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की। सरकार इस वित्त वर्ष में 8,000 मेगाहट्र्ज की देश की सबसे बड़ी नीलामी करने को इच्छुक है।

हो सकता है फैसला

- डीसीसी की अगली बैठक में स्पेक्ट्रम के नीलामी प्रस्ताव पर हो सकता है विचार
- उम्मीद की जा रही है कि दूरसंचार समिति ट्राई के सुझावों को मंजूरी देगी
- सरकार ने 2017-18 और 2018-19 वित्त वर्ष में स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की

दूरसंचार क्षेत्र को राहत देने पर विचार के लिए गठित समिति भंग

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 25 नवंबर

सरकार से जुड़े एक सूत्र ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को राहत पैकेज देने पर गौर करने के लिए पिछले महीने गठित सचिवों की समिति को भंग कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के एजीआर नियमन को अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे आईएसपी पर लागू करने के मसले पर सूत्रों ने कहा कि जहां इन मामलों को अलग रखा जाएगा और ऐसी कंपनियों को मामले में पक्ष नहीं बनाया गया था, इसलिए उन्हें वैधानिक बकाये के भुगतान की बाध्यता नहीं है।

यह पूछे जो पर कि क्या सचिवों की समिति को भंग कर दिया गया है, सूत्र ने सकारात्मक जवाब दिया। बकाया मसलों के समाधान के लिए नई अंतरमंत्रालयी समिति गठित करने के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा, 'नहीं, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित मसला है।'

मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में अक्टूबर में गठित सचिवों की समिति को दूरसंचार कंपनियों के वित्तीय दबाव से संबद्ध सभी पहलुओं पर गौर करना तथा उसमें कमी लाने को लेकर उपाय सुझाने थे। समिति को यह काम सौंपा गया था कि वह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की मांग पर विचार करे, जिसमें भुगतान टालने और एयरवेव्स का उपभोग शुल्क कम करने पर विचार करना शामिल था। समिति को युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) में कंपनी के सालाना राजस्व का 5 प्रतिशत अंशदान करने की बाध्यता के मसले पर भी विचार करना था।

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो के लिए स्पेक्ट्रम भुगतान बकाया दो साल के लिए टाल दिया गया था और उनसे उम्मीद की गई थी कि वे नीलामी में मिले स्पेक्ट्रम की कीमत का भुगतान सालाना किस्तों में करेंगे।

सूत्रों ने कहा कि सरकार के इस कदम से भारतीय एयलटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी, वहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा वैधानिक भुगतान अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद सरकार इस मसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 1.4 लाख करोड़ रुपये वैधानिक बकाये का भुगतान करना पड़ेगा। शीर्ष न्यायाल ने 24 अक्टूबर को अपने आदेश में संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को झटका दिया था, जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए शुल्क को लेकर जंग कर रही हैं।

पिछले महीने शीर्ष न्यायालय ने गैर-दूरसंचार इकाइयों से आय समेत दूरसंचार कंपनियों की सालाना समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को लेकर सरकार के रुख को बरकरार रखा था, जिसके एक हिस्से का भुगतान लाइसेंस और स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में किया जाना है।

राजीव गौबा समिति भंग

- दूरसंचार कंपनियों को राहत पैकेज देने पर गौर करने के लिए गठित सचिवों की समिति भंग
- समिति का गठन उच्चतम न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद किया गया था
- न्यायालय ने गैर-दूरसंचार इकाइयों से आय समेत दूरसंचार कंपनियों के सालाना समायोजित सकल राजस्व पर सरकार का रुख बरकरार रखा था
- सूत्रों ने कहा कि जिन कंपनियों को एजीआर मसले पर न्यायालय में पक्ष नहीं बनाया गया था, उन्हें वैधानिक बकाये के भुगतान की बाध्यता नहीं

घरेलू उद्योगों को निगम से ऑनलाइन मिलेगी मंजूरी

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 25 नवंबर

दिल्ली में घरेलू श्रेणी में आने वाले 112 तरह के उद्योगों की कारोबार की राह आसान होने जा रही है। इन उद्योगों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है। निगम ने इन घरेलू उद्योगों को कारोबारी सुगमता प्रदान करने के लिए जरूरी लाइसेंस ऑनलाइन देने की सुविधा शुरू की है। उत्तरी नगर निगम ने घरेलू उद्योगों की नई परिभाषा के तहत लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल की शुरुआत की।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और उत्तरी नगर निगम महापौर अवतार सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस बीच, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की महापौर अंजू कमलकांत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीलिंग का डर दिखाकर घरेलू उद्योगों और प्रदूषण नहीं फैलाने वाले फैक्टरी मालिकों को परेशान न करें। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ वे सख्त कार्रवाई के पक्ष में हैं। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में घरेलू उद्योगों की नई परिभाषा को मंजूरी दी है। इसके तहत 9 कामगार और 11 किलोवॉट बिजली मीटर कनेक्शन क्षमता वाले उद्योगों को घरेलू श्रेणी में माना जाएगा। घरेलू उद्योगों को रिहायशी इलाकों में चलने की अनुमति है।

- उत्तरी नगर निगम की लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सुविधा
- दिल्ली विधानसभा के शीत सत्र में पेश होंगे कौशल, उद्यमिता और खेल विश्वविद्यालय विधेयक

बीएस सूडोकू 3596

	4	1	2				6	
6		9					2	
	8		4					1
7			3	9				
	3		7		8		1	
				4	2			7
8					5		3	
	5					1		4
	2				4	6	5	

परिणाम संख्या 3595

2	7	1	6	4	5	9	3	8
3	6	5	7	8	9	2	4	1
4	8	9	3	2	1	5	6	7
7	2	6	1	9	3	4	8	5
8	9	4	2	5	7	3	1	6
5	1	3	8	6	4	7	9	2
9	5	7	4	1	6	8	2	3
6	3	8	9	7	2	1	5	4
1	4	2	5	3	8	6	7	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2125/2130, जौ 1825/1830, चावल मसूरी 2300/2350, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4200/4225, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1530/1600,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2145/2150, गेहूं शरबती 2750/2850, चावल शरबती सेला 3800/3850, स्टीम 4200/4250, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2950,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1415, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1510, फ्लैक 1445, डीएमओ 1010, टरपीन लेस बोल्ड 1540

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 1000/1050, खुरपा 920/940,चाकू 900/1030, रसकट 825/840, शक्कर 1050/1080, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3410, बुंदकी 3310, बुढ़ाना 3370, शामली 3320,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 900/920, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4225, खल: सरसों 2200/2300, बिनौला 2600/2700, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5700/5900, गेहूं (मिल) 2180/2190, मक्की 2070/2075, बाजरा 1820/1825, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3900, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4540/4550,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 4000/4025, जौ 2050/2055,

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4200/4250, ग्वारगम 7900/8000, बाजरा (गुजरात) 1900/1950, बाजरा (जयपुर) 1900/1920, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6000/6300,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)124, राइसब्रान (अखाद्य) 121, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8100, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7800/8500, उड़द धोया 10500/11500, छिलका 10500/12300, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6150/6250, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4200/4300, चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3890/3915, हरियाणा 3890/3900, राजस्थान 3850/3900, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2550/2650, सरसों खल 2180/2200,

फाजिल्का
गेहूं 2160/2170, सरसों 4225/4275 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3850/3900,कपास देशी 4850/4900, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5100, बिनौला (टैक्सपेड): खल 3200/3300,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2160/2170, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2125/2130, बिहार 2250/2300, दाल उड़द छिलका 9800/10800, चना देशी 5250/5350, दाल चना 5350/5450, काबली चना 5300/6000, राजमां चित्रा पुणे 7500/8800, चीन 7400/8000,

करनाल
गेहूं दड़ा 2165/2175, बासमती चावल 6400/6600, धान 1121 नं. 2800/2900, पूसा 1509 धान 2600/2700, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 5000/5100, स्टीम 6100/6200,

हिसार
ग्वार 4000/4050, सरसों 3950/4000, गेहूं 2140/2150, नरमा कपास 5000/5100

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1100, मैदा 1175/1200, देशी घी (एक ली/जार) 325/460, रिफाइंड (टीन) 1375/1390,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4000/4050, खल बिनौला मोटी 2450/2600, बिनौला 2700/3100, सरसों तेल 8575/8625, गेहूं 2125/2175, जौ 1825/1850, बाजरा 1800/1900

एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 240

अग्रगामी कदम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत सप्ताह औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। अब इसे चर्चा के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह विधेयक केंद्रीय श्रम मंत्रालय के देश के श्रमिकों से संबंधित कई मौजूदा कानूनों को सहज बनाने और संहिताबद्ध करने के वर्ष भर पुराने प्रयासों का हिस्सा है। इसके अलावा भी कई संहिताओं की योजना है। उनमें से एक वेतन और पेंशन से संबंधित है जिसे कानून में परिवर्तित किया जा चुका है। इसके अलावा एक अन्य का संबंध काम करने की परिस्थितियों से है और उस पर सदन में चर्चा चल रही है। चौथी संहिता सामाजिक सुरक्षा पर होगी और उसके राजकोषीय निहितार्थों पर करीबी नजर होगी। परंतु औद्योगिक संबंधों पर आधारित इस संहिता की बात करें तो यह सर्वाधिक अपेक्षित में से एक है। तमाम नियोक्ता और अर्थशास्त्री लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि इस कानून में संशोधन करके श्रम बाजार को लचीला बनाया जाए। रोजगार में छंटनी के मामले में भारत दुनिया के सर्वाधिक प्रतिबंधित नियमन वाले बाजारों में से एक है। माना जाता रहा है कि देश में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश को हतोत्साहित करने की यह एक बड़ी वजह है।

बहरहाल, विधेयक कुछ मामलों में कमजोर नजर आता है। यह एक तरह से यथास्थिति का दोहराव है। बड़े नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को रखने और निकालने को आसान बनाने संबंधी मूल प्रश्न का सीधे समाधान नहीं किया गया है। 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां अभी भी नियमित कर्मचारियों को बिना सरकारी मंजूरी के नहीं निकाल सकतीं। बहरहाल, संहिता अधिसूचना के माध्यम से 100 कर्मचारियों वाली सीमा को परिवर्तित करने की इजाजत देती है। यह मौजूदा रुख के अनुरूप ही है जिसके तहत राज्यों को श्रम कानूनों में बदलाव की इजाजत है और इसे बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की जाती है। बहरहाल, श्रम कानूनों में एक संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के बदलाव का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। यदि ऐसा होता है देश में कारोबारी सुगमता की स्थितियों में काफी सुधार होगा।

नियमित कर्मचारियों की छंटनी में मुश्किल के चलते अनुबंधित श्रमिकों की तादाद बढ़ रही है। देश की कई फैक्टरियों में नियमित कर्मचारी और अनुबंधित कर्मचारी समान काम करते हैं लेकिन अनुबंधित श्रमिकों को तुलनात्मक रूप से बहुत कम लाभ मिलते हैं। इसके खिलाफ तमाम न्यायिक निर्णयों के बावजूद यह व्यवस्था कायम है। संहिता ने अनुबंधित श्रम के इस्तेमाल को नियमित करने का काम किया है, बशर्ते कि कर्मचारियों को बीमा और छुट्टियों के मुद्रीकरण जैसे सांविधिक लाभ मिलते रहें। इससे अनुबंधित श्रम के नियोक्ताओं की लागत बढ़ेगी। सवाल यह है कि उत्पादकों की प्रतिक्रिया समग्र रोजगार में कमी के रूप में सामने आएगी या नियमित कर्मचारियों की तादाद बढ़ेगी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियां इन कर्मचारियों को सीधे नियुक्त कर सकेंगी और ठेकेदारों की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

एक मसला नौकरी से निकाले जाने वालों के हर्जाने का भी है। बहरहाल यदि श्रम बाजार में लचीलापन होगा तो निकाले जाने वाले श्रमिकों को हर्जाना भी अच्छा मिलेगा। इस मोर्चे पर नई संहिता कमजोर साबित होती है। परंतु तमाम कमियों के बावजूद कुल मिलाकर यह एक महत्त्वपूर्ण अग्रगामी कदम है। यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि चूंकि एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद कर्मियों की छंटनी के लिए सरकार की मंजूरी की सीमा में बदलाव आ जाएगा तो उस स्थिति में कार्यपालिका को इस बदलाव को देशव्यापी स्वरूप प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

अजय मोहंती

आरसेप से दूर रहकर गंवा दिया बड़ा मौका

तुलनात्मक बढ़त बनाने की प्रक्रिया में कुछ क्षेत्र पीछे छूट जाएंगे। हालांकि यह एफटीए ही नहीं बल्कि सभी तरह के व्यापार में होता है। आरसेप के बहाने एफटीए पर रोशनी डाल रही हैं **अमिता बत्रा**

भारत ने 16 देशों वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) समझौते का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर जुड़ी चिंताओं, सेवा क्षेत्र के उदारीकरण, पेशेवरों की आवाजाही से संबंधित मोड-4 और चीन एवं आसियान देशों के साथ व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका ने भारत को इस प्रस्तावित समझौते से दूर रखा है। अब हम दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा के अलावा अन्य देशों के साथ एफटीए पर नए सिरे से विचार करने की भी सोच रहे हैं। मौजूदा समय एफटीए, खासकर आरसेप के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए मुफीद हो सकता है।

पहली और सबसे खास बात, हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि एशिया में बहुत बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते होना अपरिहार्य है। समान सोच वाले देश इन समझौतों का इस्तेमाल साझा हितों को साधने और मध्यवर्ती एवं अंतिम उत्पादों की आवाजाही को संभव बनाने के लिए नियम एवं अनुशासन विकसित करने के लिए करते हैं। यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के लिए अनिवार्य है। आरसेप ऐसा ही एक विशाल क्षेत्रीय व्यापार समझौता है और इसका हिस्सा बनने से भारत क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अंग बन सकता था। पूर्व एशिया वैश्विक वित्तीय संकट खत्म होने के बाद जीवीसी गतिविधियों का सबसे गतिशील केंद्र रहा है और इस अवधि में पूर्वी एशिया के साथ यूरोप एवं उत्तर अमेरिका दोनों की ही जीवीसी गतिविधियां बढ़ी हैं।

दूसरी, व्यापार समझौते आपसी लेन-देन के सिद्धांत पर काम करते हैं। जहां यह सच है कि समझौते के सदस्य देशों को स्वाभाविक तौर पर बाजार तक पहुंच मिलती है, वहीं यह बात सभी सदस्यों पर लागू होती है। अगर हम कुछ वरीयता देते हैं तो हमें कुछ वरीयता मिलती भी है। जहां मौजूदा (स्थिर) तुलनात्मक बढ़त तरजीही पहुंच के लिए होने वाली एफटीए चर्चा का आधार है, वहीं हमें गतिशील तुलनात्मक बढ़त के लिए भी तैयार होना चाहिए। जीवीसी में शामिल होने से उत्पादों की तुलना में छोटे मध्यवर्ती कार्यों में तुलनात्मक बढ़त बना पाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस तरह, इस प्रक्रिया में विनिर्माण एवं संबद्ध सेवा गतिविधियों में नई तुलनात्मक बढ़त विकसित एवं पल्लवित हो सकती है। लिहाजा यह जरूरी है कि एफटीए पर चर्चा महज स्थिर धारणाओं के बजाय गतिशील तुलनात्मक बढ़त अनुमानों पर आधारित होनी चाहिए।

तुलनात्मक लाभ की स्थिति पैदा करने के क्रम में कुछ क्षेत्रों को नुकसान उठाना होगा। वैसे यह बात केवल एफटीए पर ही नहीं लागू होती है, सभी तरह के व्यापार में ऐसा होता है। एफटीए समझौतों में व्यापार उदारीकरण और खासकर तरजीही उदारीकरण के साथ श्रम क्षेत्र के लिए मददगार नीतियों एवं कार्यक्रमों की भी जरूरत होती है ताकि नुकसान उठाने वाले क्षेत्रों में व्यापार-जनित विस्थापन को समायोजित किया जा सके। जापान, दक्षिण कोरिया एवं वियतनाम जैसे देशों ने व्यापार सहयोग के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाए हुए हैं। पुनर्प्रशिक्षण, स्थानांतरण भत्ता, शिक्षा और वित्तीय सहायता के साथ छोटी एवं मझोली इकाइयों और उनके कामगारों को समर्थन देकर मुक्त व्यापार समझौतों और आर्थिक सुधार के दुष्प्रभावों से निपटने की कोशिश की गई है।

तीसरी बात, व्यापार घाटे के संदर्भ में यह लाभप्रद हो सकता है कि जीवीसी के दौर में वस्तुओं के उत्पादन में तीसरे देश की सहभागिता को नहीं जोड़ने वाली आयात-निर्यात की साधारण गणना द्विपक्षीय व्यापार घाटों का सबसे सटीक अनुमान नहीं हो सकती है। यह देखते हुए कि चीन कई देशों के लिए असेंबलिंग एवं पुनर्निर्यात का एक केंद्र है, लिहाजा मूल्य वर्द्धन के आधार पर एक व्यापार संतुलन अनुमान एक उपयोगी कवायद हो सकती है। इससे हम चीन के साथ अपने व्यापार असंतुलन की अधिक सटीक तस्वीर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा निर्यात एवं व्यापार पुनर्संतुलन में वृद्धि वांछनीय उद्देश्य होते हुए भी प्रत्याशित सुनिश्चित परिणाम नहीं है। एफटीए का फायदा उठाने के लिए भारत को घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना, बड़े बाजार सुधार करना और एक अनुकूल व्यापार एवं निवेश परिवेश बनाना जरूरी है। वियतनाम जैसे छोटे देशों ने ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी समझौते में सदस्य बनने की मंशा जताई है ताकि उसे आरसेप की तुलना में कहीं अधिक एकीकरण का लाभ मिल सके और घरेलू आर्थिक सुधारों को अमलीजामा पहनाया जा सके।

चौथी बात, भारत के लिए सेवा क्षेत्र वार्ताओं में उदारीकरण के साधनों से परे जाकर सोचना उपयोगी हो सकता है। आसियान का सीमित आंतरिक सेवा क्षेत्र उदारीकरण और सेवाओं में भारत-आसियान एफटीए का लागू नहीं होना आसियान को राजी करने की राह में आने वाली मुश्किलों का संकेत होना चाहिए। व्यवसाय, वित्तीय, परिवहन एवं लॉजिस्टिक जैसे मूल्य-श्रृंखला उत्पादन के लिए जरूरी या उनके साथ-साथ चलने वाली सेवाएं या शोध एवं डिजाइन जैसी उच्च सेवाएं भी आरसेप में शामिल होने के बाद नए अवसर पैदा कर सकती हैं। इन क्षेत्रों में अपने संभावित तुलनात्मक लाभ को चिह्नित करने से बातचीत की प्रक्रिया में कुछ लचीलापन आ सकेगा।

पांचवीं बात, आसियान के साथ भारत के एफटीए के मामले में एक निम्न उपयोगी दर एफटीए प्रभावहीनता या व्यापार पर असर डालने की सीमित क्षमता का अनिवार्य रूप से संकेतात्मक नहीं है। यह कारोबारी लोगों की एफटीए के बारे में सीमित समझ के आधार पर भी हो सकता था। तरजीही मार्जिन एवं स्रोत के नियम के साथ सरकारी प्रयासों एवं उद्योग खासकर एसएमई को सलाह देने से दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एफटीए उपयोगी दरें बढ़ाने में मदद मिली है। भारत की ही तरह कोरिया भी एफटीए प्रक्रिया का हिस्सा बाद में ही बना है। एफटीए से व्यापार बढ़ने एवं लाभ बढ़ने को लेकर बने संदेहों को सरकारी कदमों ने गलत ठहराया है। कंपनियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाना, एफटीए पोर्टलों के जरिये सूचना का प्रसार, कार्यशालाओं का आयोजन एवं रोजमर्रा की सलाह के लिए व्यवस्था बनाना जैसे कदम सरकार उठाती है।

छठी बात, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए करना आरसेप का स्थानापन्न नहीं हैं क्योंकि फिलहाल ये दोनों क्षेत्र वृद्धि या जीवीसी गतिविधियों के मामले में दुनिया के सबसे गतिशील इलाके नहीं हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अमेरिका की दूसरे देशों के साथ व्यापार वार्ताएं बेहद अप्रत्याशित राह पर रही हैं। भारत के साथ एफटीए को लेकर तो अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। वहीं यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर वार्ता 2007 में शुरू हो गई थी लेकिन 12 साल और कई दौर की बैठकों के बाद भी इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। यूरोपीय संघ से वार्ता में सबसे जटिल मुद्दे आरसेप की ही तरह कृषि, सेवाओं का मोड-4, डेयरी क्षेत्र और बौद्धिक संपदा अधिकार के उदारीकरण के हैं। आखिरी और शायद सबसे अहम बात, आसियान-केंद्रित आरसेप समझौते में भागीदारी का मौका गंवा देना हिंद-प्रशांत की आसियान-केंद्रित संरचना में हमारी प्रासंगिकता को काफी मुश्किल बना सकता है।

ऐसे में, आरसेप के बारे में थोड़े पुनर्विचार और अगले दो महीनों में व्यापार विशेषज्ञों की मदद से बहुपक्षीय रणनीति तैयार करने और आर्थिक सुधारों को लागू करना वक्त का तकाजा है।

(लेखिका जवाहरलाल नेहरू के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में प्रोफेसर हैं)

संप्रग, राजग और बुरी खबर का दौर

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

जरा इस बारे में विचार कीजिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को अपने दूसरे कार्यकाल में वैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को 2009 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद करनी पड़ी थीं। कोई सप्ताह ऐसा नहीं बीतता जब कोई बुरी खबर नहीं मिलती हो। अंतर केवल यह है कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय व्यापक भ्रष्टाचार ने समस्या पैदा की थी जबकि मोदी सरकार के दौर में अर्थव्यवस्था इसकी वजह है। एक के बाद एक बुरी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। उस वक्त डॉ. सिंह असहाय प्रतीत हो रहे थे और लगभग लड़खड़ा रहे थे। निजी तौर पर वह भ्रष्ट नहीं थे बल्कि वह तो इससे कोसों दूर थे। परंतु उनके साथ काम करने वालों ने उन्हें नीचा दिखाया।

मोदी के साथ भी ठीक यही बात है। छह वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें अब तक इस बात का अंदाजा नहीं हो सका है कि आखिर कहां क्या गड़बड़ी है। सन 2013 तक यानी मनमोहन सिंह की सरकार के अंतिम पूर्ण वर्ष के दौरान आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबरों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया था। इसका सबसे अधिक राजनीतिक फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। मतदाताओं ने उनके हर वादे पर यकीन किया।

वर्ष 2012 में मुद्रास्फीति की जो भूमिका संप्रग के लिए थी यदि 2022 में भ्रष्टाचार राजग के लिए उसी भूमिका में आ जाता है तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

संप्रग की छवि साफ-सुथरी करने की कोशिश में डॉ. मनमोहन सिंह ने कई जांच और दंडात्मक कार्रवाइयों की घोषणा की। परंतु इनसे कोई मदद नहीं मिली। मोदी ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर जल्दबाजी में ऐसी ही घोषणाएं की हैं और आगे भी करेंगे। यह तो समय ही बताएगा कि इससे कोई मदद मिलती है या नहीं।

वर्ष 2012 के आखिर तक संप्रग के गैर कांग्रेसी सदस्यों ने लगभग समर्पण कर दिया। उनमें से कई ने मुझसे कहा कि वे अब आराम करना चाहते हैं और अपने नाती-पोतों के साथ खेलना चाहते हैं। राजग के साझेदारों को भी भाजपा के साथ वही समस्या है। एकता की जगह विविधता ले रही है। स्पष्ट है कि राजनीतिक आवश्यकताएं किसी की प्रतीक्षा नहीं करतीं। यह याद करना भी उचित होगा कि सन 2010 में भाजपा पूरी तरह निराश थी और कांग्रेस को साफ बढ़त नजर आ रही थी। परंतु 2014 आते-आते हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

कांग्रेस की स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उसकी छवि के साथ अक्षमता और कुटिलता जैसी बातें जुड़ गईं। अवधारणाएं इसी प्रकार बनती हैं। उनमें तथ्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता।

मोदी सरकार फिलहाल इसी समस्या से जूझ रही है। आम धारणा यह है कि सरकार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था के औद्योगिक उत्पादन में अचानक आ रही भारी गिरावट की समस्या से कैसे निपटा जाए। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 15 फीसदी है।

यहां तक कि जब सरकार सही कदम उठाती है तब भी सरकार की आलोचना की जाती है। निश्चित रूप से सच यह है कि सरकार ने वही कदम उठाए हैं जो अर्थशास्त्रियों तथा वृहद, सूक्ष्म, कराधान तथा प्रशासनिक मामलों से जुड़े अन्य विशेषज्ञों ने सुझाए।

सरकार की कदम उठाने की गति भले ही निराश करने वाली हो, लेकिन उसकी दिशा गलत नहीं है। परंतु जनता का मिजाज ऐसा हो चुका है कि वह क्षमा करने के मूड में नहीं है। एक बार अगर जनता की धारणा बन गई तो सरकार जिन सीमाओं के भीतर काम कर रही है, वे केवल एक बचाव की तरह नजर आएंगी।

एक बड़ी पहेली जिसके बारे में मैं पहले भी लिख चुका हूं, वह है सरकार की राजनीतिक नीतियों और आर्थिक नीतियों के बीच कोई तालमेल न होना। राजनीति में बड़ी चीजों के बारे में बातें और उससे जुड़ी अवधारणाएं चुनाव जीतने में मददगार साबित हो सकती हैं।

यह संप्रग से उलट है। उसके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सही दिशा में थी। कम से कम तब तक जब तक प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री नहीं बन गए। उनके वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया यह वही बता सकते हैं।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की तरह मोदी सरकार को भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है जहां सारी गड़बड़ियां एक साथ घटित होती हैं। यह एक ऐसी नाव की तरह हो चुकी है जिसमें सैकड़ों छेद हो चुके हैं। नौका चालक दल को यह पता नहीं है कि नाव से पानी बाहर निकालना है या छेद भरने हैं।

औद्योगिक वस्तुओं की मांग में फिलहाल जो कमी आई है वह काफी हद तक ऐसी ही है। सरकार उपभोक्ताओं की मांग और निवेश पर व्यय बढ़ाने की दिशा में खूब प्रयास कर रही है लेकिन सबकुछ सही नहीं हो पा रहा है।

ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार के पास केवल एक ऐसा उपाय है जो आर्थिक रूप से समझदारी भरा माना जा सकता है: वह है व्यय में कटौती करना। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास धन की कमी है। परंतु ऐसा करते हुए भी उसे संप्रग सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। चिदंबरम ने व्यय को छिपाने और लंबित करने का तरीका अपनाया था।

निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं और निवेशकों के रुझान में आई भारी कमी के लिए सरकार का बहुत अधिक खर्च करना भी उत्तरदायी है। इसके अलावा सरकार कर राजस्व भी चाहती है। सरकार को थोड़ा सहज रहने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्री कींस की बातों को याद करें तो इस समय अर्थव्यवस्था में जो कुछ हो रहा है वह उनके द्वारा सोचे गए तौर तरीकों से एकदम उलट है।

जब चीजें उस तरह नहीं घटित होतीं जैसे उन्हें होना चाहिए तब वैसी स्थिति बनती है जैसी अभी बनी हुई है। उस स्थिति में गति को धीमा करना होता है।

कानाफूसी

आरोप-प्रत्यारोप

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं। सन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मौर्य को प्रदेश के नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था। हाल ही में दोनों नेताओं के रिश्तों के बीच का ठंडापन उस समय सार्वजनिक हो गया जब मौर्य ने आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। चूंकि आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय के प्रभारी भी हैं इसलिए प्रदेश के विकास प्राधिकरणों का नेतृत्व भी उनके ही पास है। बहरहाल इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में सड़कों की खस्ता हालत का मुद्दा उठा दिया है। मौर्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं जो प्रदेश की सड़कों के रखरखाव का उत्तरदायी है।

श्रेय में साझेदारी

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा श्रेय लेकर उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि वह इस योजना के अधीन बनने वाले आवासों पर ऐसे टाइल्स लगाएगी जिन पर लिखा होगा कि इस आवास के निर्माण में 40 फीसदी योगदान राज्य सरकार का है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार केवल नए बनने वाले आवासों पर यह लिखवाने जा रही है बल्कि जो आवास पहले से बन चुके हैं उन पर भी ये टाइल्स जुड़वाई जाएंगी। राज्य सरकार इस दिशा में पहल भी कर चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 86 हजार घरों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी टाइल्स को घरों में लगाने की बात सामने आई थी।

आपका पक्ष

अंगदान जीवनदान लेकिन दान में कमी

कई बार देखा गया है कि अंग नहीं मिल पाने की वजह से मरीज की जान नहीं बच पाती है। कोई व्यक्ति किसी अंग के इंतजार में अपनी जान गंवा देता है। देश में आज भी अनेक लोग अंगदान नहीं करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु के बाद अपने परिजन का अंगदान नहीं करने देते हैं। उन्हें लगता है कि सभी अंग के बगैर अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस रूढ़िवादी अवधारणा के कारण अनेक लोगों का अंगदान नहीं हो पाता है जिससे किसी अंग के इंतजार में बैठे मरीज की जान चली जाती है। हालांकि पिछले तीन साल में अंगदान के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई तो है लेकिन यह आशा के अनुरूप नहीं है। सरकार के अनुसार अंगदान के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के कारण पिछले तीन साल में अंगदान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है लेकिन देश के 28 राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश में से 22 में ही अंगदान शुरू हो पाया है। अंगदान के मामले में दिल्ली शीर्ष पर है लेकिन बिहार सबसे पीछे है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में 9,046 अंगदान हुए थे जो वर्ष 2018 में बढ़कर 10,387 हो गए। यह आंकड़ा वर्ष 2016 में 1,947 और वर्ष 2017 में 1,989 था। इसमें मुख्य रूप से गुर्दा, हृदय, फेफड़े और कॉर्निया के अलावा स्टेम सेल का अंगदान किया जाता है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अंगदान करने में शीर्ष पर दिल्ली, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अंगदान काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आधुनिकता के कारण लोगों की जीवनशैली बदल गई है जिससे लोग गंभीर रोग की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के अंग से किसी अन्य व्यक्ति को जीवनदान मिल रहा है तो हमें अंगदान करना चाहिए। आज अगर कोई व्यक्ति अंगदान करता है तो भविष्य में उनके परिवार को भी किसी अन्य व्यक्ति से अंगदान मिल सकता है। अत: लोगों को अंगदान करने में आगे आना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति असमय मौत का शिकार न हो।

किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से किसी दूसरे व्यक्ति को जीवनदान मिल सकता है

कृतिका सिंह, नई दिल्ली

वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा हो

देश की अदालतों में कई मामले वर्षों से लंबित हैं जिनके निपटारे के लिए अदालत के साथ-साथ सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को अदालत को सुविधाएं, आधारभूत ढांचा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी जिससे लंबित मामलों की सुनवाई हो सके। मामले लंबित होने के कारण आरोपी जेल में ही कई साल गुजार देते हैं। ऐसे किसी मामले में अगर आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया हो और बाद में वह निर्दोष साबित हो जाता है तो वह जितने साल जेल में गुजारता है उसकी भरपाई करना असंभव है। कोई व्यक्ति एक बार जेल चला जाता है तो समाज में उनके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। समाज में तरह-तरह की बातें की जाती हैं। अंत में अगर वह निर्दोष साबित हो भी जाता है तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल पाती है। सरकार को अदालतों की संख्या बढ़ाने, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, अदालत में काम करने वाले कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

शिवम कुमार, लखनऊ

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

चीनी टायर फेब्रिक की डंपिंग जांच

भाषा
नई दिल्ली, 25 नवंबर

वाणिज्य मंत्रालय ने चीन से आयात होने वाले नाइलोन टायर कॉर्ड फेब्रिक पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा को लेकर जांच शुरू की है। मंत्रालय ने घरेलू उद्योग से मिली शिकायतों के बाद यह कदम उठाया है। एसोसएिशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री ने अपने सदस्यों एसआरएफ लिमिटेड और सेंचुरी एंका लिमिटेड ने चीन से नाइलोन टायर कॉर्ड फैब्रिक के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है। मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की एक अधिसूचना के अनुसार आवेदनकर्ताओं ने साक्ष्य पेश किया है कि चीनी कंपनियां भारत में डंपिंग कर सकती हैं।

अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण ने शुल्क जारी रखने की जरूरत की समीक्षा को लेकर जांच शुरू की है। जांच की अवधि जुलाई 2018 से जून 2019 होगी। इसके तहत 2016-19 की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इस उत्पाद पर शुल्क पहली बार अप्रैल 2015 में लगाया गया। बाद में जून 2015 में इसे फिर से पांच साल के लिए लगाया गया।

मौसम की मार से पिछड़ी रबी की बुआई

पिछले साल से रबी फसलों की बुआई 10 फीसदी और चने की बुआई 22 फीसदी कम है

सुशील मिश्र
मुंबई, 25 नवंबर

चालू रबी सीजन फसलों की बुआई पिछले सीजन की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। पिछले सीजन के मुकाबले रबी फसलों की बुआई करीब 10 फीसदी पीछे चल रही है जबकि इस सीजन की सबसे प्रमुख दलहन फसल चने की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 22 फीसदी कम है। मौसम में अनिश्चितता के कारण इस बार अबतक रबी फसलों का रकबा पिछड़ा हुआ है।

इस साल अक्टूबर से शुरू हुए रबी सीजन में फसलों की बुआई शुरुआत से ही पिछड़ी हुई है। अक्टूबर में हुई बेमौसम बारिश और खरीफ फसलों में हुई देरी को रकबा कम होने की वजह बताया जा रहा है। खरीफ फसलों की देरी के चलते रबी सीजन की फसलों की बुआई देरी से शुरू हुई। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 22 नवंबर तक 251.04 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई जबकि पिछले साल इस अवधि तक 276.83 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हो चुकी थी। इस सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की बुआई अभी भी पिछले साल से कम है।

आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में अबतक 96.77 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान 99.64 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो चुकी थी। दो सप्ताह पहले तक गेहूं की बुआई काफी पीछे थी। लेकिन तेज बुआई के कारण यह आंकड़ा पिछले साल के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी गेहूं का रकबा पिछले साल के मुकाबले 2.87 लाख हेक्टेयर कम है। पंजाब और मध्य प्रदेश में रकबा कम होने के कारण गेहूं की बुआई पिछले साल से पीछे चल रही है।

चालू रबी सीजन में दलहन फसलों की बुआई सबसे अधिक पिछड़ी है। दलहन फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 20 फीसदी कम है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अबतक 71.26 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक 88.27 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। दलहन फसलों की सबसे प्रमुख फसल चने की बुआई सबसे कम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी रबी फसलों की बुआई के आंकड़े के अनुसार देशभर में चने की बुआई अबतक 48.35 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल चने का रकबा 61.91 लाख हेक्टेयर था।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि चने का सही भाव नहीं मिलने और मौसम की अनिश्चितता के कारण इस बार किसान चने की जगह गेहूं जैसी दूसरी फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि अभी तक गेहूं सहित लगभग सभी रबी फसलों की बुआई पिछले साल से पीछे चल रही है।

बदलते मौसम का असर तिलहन फसलों की बुआई पर भी पड़ा है। चालू रबी सीजन में अभी तक तिलहन फसलों की बुआई कुल 54.88 लाख हेक्टेयर में हुई है जबकि पिछले साल रकबा 58.07 लाख हेक्टेयर था। अभी तक तिलहन फसलों की बुआई पिछले साल से 3.19 लाख हेक्टेयर कम है।

इस सीजन की सबसे प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली का रकबा पिछले साल से 2.92 लाख हेक्टेयर कम है। अभी तक देश में 50.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की बुआई हुई है। चालू रबी सीजन में मोटे अनाजों की बुआई अभी तक 21.33 लाख हेक्टेयर में हुई है जो पिछले साल से 2.67 लाख हेक्टेयर कम है। पिछले साल इस समय तक बुआई 24 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी।

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक फसलों की बुआई ने रफ्तार पकड़ी है उम्मीद है कि नवंबर खत्म होते होते बुआई का रकबा पिछले साल के करीब पहुंच जाएगा।

कम हुआ रकबा

- देश में 22 नवंबर तक 251.04 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई, पिछले साल 276.83 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी
- इस सीजन में गेहूं की बुआई 96.77 लाख हेक्टेयर में हुई, पिछले साल 99.64 लाख हेक्टेयर में हुई थी
- दलहन फसलों की बुआई 71.26 लाख हेक्टेयर में हुई, पिछले साल 88.27 लाख हेक्टेयर में हुई थी

2025 तक कागज की खपत 2.4 करोड़ टन रहने के आसार

भाषा
नई दिल्ली, 25 नवंबर

इस समय 1.5 करोड़ टन है खपत

भारतीय कागज उद्योग का अनुमान है कि देश में कागज उद्योग औसतन सालाना 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकता है और इसके साथ अगले पांच साल में 2024-25 तक कागज की घरेलू खपत 2.4 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। कागज विनिर्माताओं के संघ इंडियन पेपर ऐंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस समय कागज की खपत 1.5 करोड़ टन है।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सेंचुरी पेपर के मुख्य कार्याधिकारी जेपी नारायण ने राजधानी में अगले सप्ताह आयोजित की जा रही कागज उद्योग की प्रदर्शनी पेपरएक्स 2019 से पहले विज्ञप्ति में कहा कि कागज उद्योग बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कुछ बड़ी कागज कंपनियां अपने किसी क्षेत्र, उत्पाद या श्रेणी विशेष की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी देश में कागज की कुल खपत डेढ़ करोड़ टन है जिसके 2024-25 तक बढ़कर 2.4 करोड़ टन होने का अनुमान है। नारायण ने कहा कि इस उद्योग की सालाना वृद्धि करीब 12 प्रतिशत रहने की उम्मीद हैं। पेपरएक्स, कागज उद्योग से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। इस साल यह 3-6 दिसंबर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की जा रही है। विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। कागज उद्योग क्षेत्र के वैश्विक समूह एशियाहाइव ग्रुप के क्षेत्रीय निदेशक गार्डन पेनी ने कहा कि भारत को पेपरएक्स उद्योग प्रदर्शनी के आयोजन पर वास्तव में गर्व होना चाहिए। यह उद्यमियों को इस उद्योग के ताजा रुझानों और प्रौद्योगिकी को एक साथ देखने समझने तथा नए पुराने उद्यमियों को आपस में मिलने का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराती है।

संघ ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस प्रदर्शनी में 28 देशों के 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रदर्शनी में करीब 30,000 कारोबारी आगंतुकों के आने का अनुमान है। कागज उत्पादन से जुड़े देशभर के 1,100 से अधिक लघु उद्योग (एमएसएमई) पहली बार इस प्रदर्शनी में शामिल होंगे। नारायण ने कहा कि मेरा मानना है कि देश में इस उद्योग के अंदर विलय और एकीकरण के रुझान बढ़ेंगे। हमें अधिक कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण देखने को मिल सकते हैं। चूंकि इस उद्योग में श्रमबल की आवश्यकता होती है, इसलिए उद्योग के विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेगा। वर्तमान में देश में 462 कागज मिलें हैं। यह हर साल करीब तीन करोड़ टन कागज का उत्पादन करती हैं। पिछले तीन साल में देश का कागज निर्यात 6.6 लाख टन से बढ़कर 15 लाख टन हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Nov 25	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,750.0	0.2	1,854.2	-5.8
Copper	5,834.0	2.8	6,134.1	-1.2
Nickel	14,400.0	-8.6	15,335.3	-4.0
Lead	1,958.0	-6.0	2,119.1	3.3
Tin	16,360.0	1.9	17,077.9	-0.5
Zinc	2,315.0	2.4	2,662.8	4.3
Gold ($/ounce)	1,457.1*	-4.6	1,642.1	0.6
Silver ($/ounce)	16.9*	-3.1	19.2	0.9
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	62.9*	7.8	64.2	7.9
Natural Gas ($/mmBtu)	2.6*	20.0	2.6	20.3
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	184.0	12.2	300.7	3.6
Maize	181.7*	-0.9	299.7	-1.7
Sugar	339.7*	9.4	484.6	0.2
Palm oil	650.0	18.2	1,036.9	20.1
Rubber	1,557.7*	5.2	1,826.3	-7.2
Coffee Robusta	1,365.0*	6.7	1,875.1	-14.1
Cotton	1,412.7	10.5	1,562.2	-9.1

* As on Nov 25, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.7& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	37.1	14165
Oil and Oilseeds	314.1	74310
Spices	1.3	14
Metal(Nov 22)		
Metal- non ferrous	5863.6	62421
Metal- precious	10750.9	550
Oil and gas(Nov 22)		
Gas	2887.7	27724
Oil	16550.6	2595

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	77.4	111987
Grains	319.6	104940
Oil and Oilseeds	810.1	454705
Others	206.0	69870
Pulses	87.0	66485
Spices	104.6	31520

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Dec 13)	2877.4	3.7
Natural Gas (Nov 25)	190.4	3.1
Zinc (Nov 29)	188.5	1.0
Gold Guinea (Nov 29)	30712.0	0.9
Zinc Mini (Nov 29)	188.2	0.9
Crude Palm Oil (Nov 29)	670.3	0.6
Lead (Nov 29)	154.2	0.5
Losers (* % Change)		
Mentha Oil (Nov 29)	1249.4	-0.8
Aluminium Mini (Nov 29)	129.5	-0.7
Silver Mini (Nov 29)	44485.0	-0.6
Silver Micro (Nov 29)	44489.0	-0.6
Silver (Dec 05)	44480.0	-0.6

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Jeera Unjha (Dec 20)	16055.0	0.9
Soyabean Indore (Dec 20)	4050.0	0.9
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1073.5	0.7
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4240.0	0.3
Maize Kharif (Dec 20)	1901.0	0.1
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	809.1	0.0
Losers (* % Change)		
Moong-Mertacity (Dec 20)	6575.0	-3.7
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7601.0	-2.9
Coriander-Kota (Dec 20)	6823.0	-2.7
Guar Seed 10 (Dec 20)	4152.5	-2.2
Wheat-Kota (Feb 20)	2178.0	-1.7
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5646.0	-1.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	3.8
Gold Petal-Mumbai (Nov 29)	3896.0	2.4
Cotton-Rajkot (Nov 29)	19050.0	2.2
Silver Micro-Ahemd (Nov 29)	44489.0	0.7
Silver Ahm (Dec 05)	44480.0	0.6
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	2877.4	0.5
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Nov 29)	1249.4	-10.4
Alumini-Mumbai (Nov 29)	129.5	-6.4
Aluminium Mum (Nov 29)	129.8	-6.1
Copper Mum (Nov 29)	430.1	-4.0
Lead Min Mumbai (Nov 29)	153.6	-1.5
Nickel Mumbai (Nov 29)	1085.2	-1.2

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Maize-Sangli (Dec 20)	1901.0	3.1
Barley Jaipur (Dec 20)	2143.0	0.9
Moong-Merta City (Dec 20)	6575.0	0.3
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18520.0	0.2
Soy Bean Indore (Dec 20)	4050.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5646.0	-5.1
Coriander-Kota (Dec 20)	6823.0	-4.6
Jeera Unjha (Dec 20)	16055.0	-2.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7601.0	-2.4
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3114.0	-2.3
Crude Palm Oil Kandl (Nov 29)	670.0	-1.6

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	95.....(95)
Aluminium ingots /kg	133.....(135)
Brass sheet cutting /kg	312.....(312)
Brass utensil scraps/kg	295.....(293)
Copper heavy scrap /kg	406.....(406)
Copper utensil scraps/kg	380.....(378)
Copper wire bar /kg	440.....(439)
Lead ingots /kg	152.....(152)
Nickel Cathodes /kg	1100.....(1085)
Tin slabs /kg	1225.....(1240)
Zinc slabs /kg	191.....(189)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10686.....(10686)
DCH - 32 /Qtl	11473.....(11473)
Jaydhar /Qtl	10292.....(10292)
Shankar- 6 /Qtl	11417.....(11417)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	905.....(905)
Castor Comm /10kg	895.....(895)
Ricebran oil/10kg	760.....(760)
Groundnut oil /10kg	1020.....(1020)
Linseed oil /10kg	845.....(845)
Karanji /10kg	800.....(800)
Palm oil /10kg	745.....(727)
Sunflower exp ref /10kg	830.....(827)
Sunflower oil exp /10kg	795.....(785)
Soyabean ref / 10kg	790.....(785)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3570 .....(3382-3570)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	57.78.....(57.77)
Brent Crude (UK)	62.92.....(62.98)
Brent Crude (WTI)	57.7.....(57.7)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.6.....(2.67)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	252.28.....(254.49)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37871.....(38157)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38023.....(38310)
Silver.999/ kg	44250.....(45000)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18435.40	18477.20
Alumini-Mumbai (M)	1 K	136.50	138.25
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1900.00	1900.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2133.50	2123.90
Brass-Jamnagar (M)	1 K	299.70	298.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2950.00	2983.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4302.20	4296.90
Castor Seed-Kadi (N)	X	4300.00	4300.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4381.25	4376.30
Chana Delhi (N)	1 Q	4522.90	4520.45
Chana-Akola (N)	X	4450.00	4471.90
Coriander-Gondal (N)	X	6800.00	6900.00
Coriander-Jaipur (N)	X	7158.35	7125.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7166.30	7148.60
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2234.55	2146.15
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2084.05	2062.15
Cotton-Kadi (N)	1 B	18381.60	18429.40
CPO-Kandla (M)	10 K	662.00	670.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	669.25	681.20
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	873.70	873.50
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1545.95	1540.75
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3488.05	3475.65
Gold Ahm (M)	10 G	38157.00	37862.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30648.00	30411.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3829.00	3804.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7900.00	7785.65
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4225.90	4141.65
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4200.00	4167.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1021.45	1010.05
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	91.25	92.05
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16900.00	17000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16493.75	16484.10
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1006.50	1009.85
Kapas-Rajkot (N)	X	995.35	994.75
Lead Mum (M)	1 K	159.60	156.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1851.25	1866.25
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2140.00	2150.00
Maize-Erode (N)	X	1868.35	1881.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2065.00	2080.00
Maize-Sangli (N)	X	1842.65	1843.35
Moong-Merta City (N)	1 Q	6621.90	6556.25
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4437.00	4501.40
Nickel Mumbai (M)	1 K	1096.50	1098.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3187.50
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3088.00	3202.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	347.00	346.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34500.00	34033.35
Rape mustards-Patan (I)	20 K	804.33	796.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2091.95	2100.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	730.50	743.75
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	797.40	805.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	789.65	798.80
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	800.00	806.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13075.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13000.00	13075.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44942.00	44194.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4003.00	4048.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3976.90	3987.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	3913.75	3964.25
Soy Bean-Akola (N)	X	3982.00	4000.00
Soymeal Indore (M)	1 T	32900.00	33300.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	790.40	805.40
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27840.00	27800.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28900.00	28700.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26000.00	25950.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3315.00	3395.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3428.55	3419.00
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3295.00	3296.25
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3514.30	3519.05
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3343.75	3357.50
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3135.45	3116.90
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5987.50	5948.70
Wheat Delhi (N)	1 Q	2281.65	2270.85
Wheat Kota (N)	1 Q	2147.35	2131.80
Wheat New Indore (N)	1 Q	2205.00	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2097.50	2080.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2240.00	2240.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4625.00	4615.20
Zinc Mumbai (M)	1 K	189.60	190.00

* as on Nov 22, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (सोमवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Nov 29	18970, 19160, 18970, 19050	1437	210	2487
Dec 31	19060, 19220, 18890, 19180	1624	273	9018
Jan 31	19240, 19320, 19240, 19300	132	22	1832
Mar 31	19500, 19500, 19500, 19500	04	1	17
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2121, 2121, 2076, 2085	15640	1039	47560
Jan 20	2095, 2104, 2072.5, 2085	13680	910	37390
Feb 20	2095, 2107.5, 2080, 2092.5	1070	97	21050
Mar 20	2121, 2123, 2095, 2103	520	48	2340
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1070, 1074, 1068, 1072.5	200	46	768
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1070, 1074, 1067, 1073.5	600	315	3647
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4242, 4245, 4134, 4152.5	53630	4020	75480
Jan 20	4264, 4275, 4168, 4188.5	22120	1666	26680
Feb 20	4241.5, 4241.5, 4191, 4217	200	20	400
Maize Kharif NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	1900, 1910, 1900, 1901	2000	7	2300
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4232, 4292, 4120, 4240	7800	844	49380
Jan 20	4256, 4322, 4160, 4272	4520	498	16325
Feb 20	4214, 4214, 4214, 4214	20	4	3290
Mar 20	4100, 4182, 4074, 4074	35	7	2260
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Nov 29	665.5, 671.9, 664.5, 670.3	14890	900	22440
Dec 31	672, 679.5, 670, 674.8	21700	1410	42360
Jan 31	675, 679.2, 673.5, 674.4	1330	113	9130
Mentha Oil MCX(1 K)				
Nov 29	1255.1, 1261, 1245.9, 1249.4	207	472	108
Dec 31	1275, 1275, 1262.3, 1263.8	259.56	653	272.16
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4355, 4367, 4331, 4340	9420	770	31810
Jan 20	4359, 4374, 4340, 4349	3090	257	3450
Apr 20	4270, 4298, 4270, 4270	60	6	720
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	809.4, 813.8, 808, 809.05	17930	1336	45380
Jan 20	812, 818.1, 811.5, 813.2	6560	476	33600
Feb 20	816.6, 820, 814, 817.05	660	52	1200
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4020, 4075, 4019, 4050	57360	4221	82000
Jan 20	4035, 4088, 4035, 4066	36490	2856	113200
Feb 20	4064, 4100, 4060, 4085	22670	1704	60130
Mar 20	4090, 4141, 4090, 4121	6160	445	11840
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7778, 7820, 7580, 7601	16715	2122	47385
Jan 20	7883, 7930, 7688, 7710	9910	1170	22310
Feb 20	8020, 8020, 8004, 8004	40	4	175
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4504, 4511, 4462, 4480	14490	1025	43290
Jan 20	4499, 4511, 4467, 4484	4440	345	22290
Mar 20	4500, 4500, 4460, 4476	440	38	700
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	6626, 6626, 6575, 6575	50	2	125
Wheat-Kota NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	2178, 2178, 2178, 2178	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	2858.1, 2885.8, 2826, 2877.4	2.4	24	5.2
Jan 15	2807.2, 2834.5, 2765, 2826.4	2.2	19	7.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	7005, 7088, 6801, 6823	4580	397	10230
Jan 20	6880, 6895, 6646, 6682	1080	103	3080
Apr 20	7190, 7200, 7070, 7148	420	40	1960
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	15980, 16100, 15840, 16055	1980	488	3102
Jan 20	15940, 15940, 15665, 15855	501	164	759
Mar 20	15605, 15650, 15550, 15615	84	22	189
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5712, 5756, 5612, 5646	2600	440	10000
Mar 20	6062, 6180, 6006, 6022	780	133	1150
Apr 20	6110, 6168, 6020, 6060	355	60	1045
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Nov 29	129, 129.95, 129, 129.35	3930	549	4110
Dec 31	131.9, 132.05, 131.5, 131.65	4500	745	7870
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Nov 29	129.85, 129.9, 128.7, 129.3	1041	661	2257
Dec 31	132, 132.2, 131.25, 131.7	1870	1373	3221
Jan 31	130.15, 133.5, 130.15, 132.8	7	7	9
Copper MCX(1 K)				
Nov 29	431, 432.8, 430.4, 431.2	5490	1699	5130
Dec 31	437.1, 437.5, 436.1, 436.8	11277.5	3634	12895
Jan 31	441.8, 442.35, 441.3, 442.05	62.5	24	507.5
Lead MCX(1 K)				
Nov 29	153.75, 155.5, 153.75, 155.05	3540	638	1730
Dec 31	154.15, 154.65, 154.15, 154.55	5240	872	5450
Lead Mini MCX(1 K)				
Nov 29	153.8, 154.35, 153.3, 154.2	760	608	528
Dec 31	154.1, 154.65, 154.1, 154.6	1605	1299	2022
Jan 31	154.5, 155, 154.4, 154.55	7	7	12
Nickel MCX(1 K)				
Nov 29	1081.7, 1087.3, 1073.2, 1079	679	1848

सेना, राकांपा, कांग्रेस का शक्ति-प्रदर्शन

राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ ही शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन 'महाविकास अघाड़ी' ने मुंबई के एक पांचसितारा होटल में मीडिया के सामने 162 विधायकों की परेड कराई

बीएस संवाददाता

शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के गठबंधन 'महाविकास अघाड़ी' ने मुंबई के एक पांचसितारा होटल में सोमवार की शाम को अपने 162 विधायकों की परेड कराने के साथ ही अपनी ताकत दिखाई। इसके पहले तीनों दलों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्याबल होने का दावा पेश किया।

तीनों दलों ने होटल में मीडिया के कैमरों के सामने अपने विधायकों की परेड कराते हुए समूचे देश को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। होटल ग्रांड हयात में शाम सात बजे तीनों दलों के विधायक इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एकजुटता बनाए रखते हुए गठबंधन सरकार बनाने का संकल्प भी जताया। विधायकों ने भाजपा के किसी भी प्रलोभन के सामने नहीं झुकने की शपथ भी ली।

शक्ति प्रदर्शन के इस मौके पर गठबंधन ने 162 विधायकों के मौजूद होने का दावा किया। विधायकों की परेड में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एवं अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे।

गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके उद्धव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती देते हुए कहा कि वे उनके विधायकों को तोड़कर दिखाएं। उद्धव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'हम सभी दोस्त हैं और कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता है।' उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा को शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए रास्ता खाली करना होगा। वहीं राकांपा प्रमुख पवार ने अपने भतीजे अजित पवार एवं भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राकांपा को तोड़ने की मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पवार ने कहा कि भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए उन राज्यों में भी सत्ता का दुरुपयोग किया जहां मतदाताओं ने उसे जनादेश नहीं दिया था। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो पाएगा।

पवार ने अपने विधायकों की तारीफ करते हुए कहा, 'कुछ लोगों ने सोचा था कि हमारे विधायकों को तोड़ लेंगे लेकिन आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे ही हम अपने गठबंधन साथियों के साथ मिलकर सरकार भी बनाएंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान के लिए किसी भी विधायक की सदस्यता न जाए, इसकी जिम्मेदारी मैं निजी तौर पर लूंगा।'

इस परेड में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। चव्हाण ने कहा, 'हम महज 162 ही नहीं, उससे भी अधिक हैं। हम सब सरकार का हिस्सा होंगे। मैं सोनिया गांधी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने भाजपा को रोकने के लिए इस गठबंधन की मंजूरी दी।'

तीनों दलों ने अपने विधायकों को टूट-फूट के डर से अलग-अलग होटलों में रखा हुआ है। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के नेतृत्व को डर सता रहा है कि पर्याप्य आंकड़े नहीं होने से शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा विधायकों को तोड़ सकती है। इस बीच सभी दलों में काफी चौकसी देखी जा रही है। राकांपा के अजित पवार ने भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का समर्थन देने के साथ शनिवार सुबह को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण के समय करीब 11-12 विधायकों के मौजूद होने की बात कही गई थी लेकिन आज राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में उनमें से भी अधिकतर विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद थे। इस तरह राकांपा अजित पवार के एकदम अलग-थलग पड़ जाने का दावा कर रही है। लेकिन इसी के साथ उन्हें मनाकर वापस लाने की कोशिशें भी अंदरखाने चलती रही हैं। अजित पवार को शनिवार शाम को ही पार्टी विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह जयंत पाटील को अंतरिम नेता बनाया गया है। जयंत पाटील दिन में शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने गए थे। तीनों दलों के नेताओं ने राज्यपाल के कार्यालय को सौंपे पत्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों के समर्थन का दावा किया। उन्होंने फडणवीस सरकार के पास बहुमत नहीं होने की बात कही और अपने गठबंधन को मौका देने का अनुरोध किया।

हालांकि भाजपा नेता आशीष शेलार ने शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा नेताओं के इस पत्र को फर्जी करार देते हुए कहा कि यह एक फर्जी पत्र है क्योंकि तकनीकी रुप से अजित पवार अभी भी राकांपा के विधायक दल के नेता हैं और उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है।

इस बीच शरद पवार ने अजित पवार के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'भाजपा के साथ जाना उनका अपना फैसला है, राकांपा का नहीं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं।' उन्होंने अजित के साथ कोई संपर्क नहीं होने की बात करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की है। उन्होंने अजित के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर कहा कि पार्टी के स्तर पर इसका निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह अचानक हुए शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो इस मसले पर विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई जबकि राज्यसभा एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से सूचीबद्ध था लेकिन महाराष्ट्र मुद्दे पर उस समय सदन में चल रहे हंगामे की ओर ध्यान दिलाते हुए राहुल ने कहा, 'महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसे में मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है।' बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया गया।

सोमवार शाम को होटल ग्रांड हयात में एकत्रित शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस पार्टी के नेता एवं विधायक *पीटीआई*

अपना-अपना दावा

- 'महाविकास अघाड़ी' गठबंधन ने किया सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल होने का दावा
- शरद पवार ने अजित पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप
- उद्धव ठाकरे ने भाजपा-अजित पवार को दी अपने विधायक तोड़ने की चुनौती
- भाजपा ने कहा, अजित अभी भी राकांपा विधायक दल के नेता
- मंगलवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा न्यायालय

अदालत आज सुनाएगी फैसला

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर उच्चतम न्यायालय मंगलवार को फैसला देगा, जबकि भाजपा और शिवसेना गठबंधन, दोनों बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। न्यायालय ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे को लेकर शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर मंगलवार को आदेश सुनाया जाएगा। इस गठबंधन ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले को चुनौती दी है। राज्य में राजनीतिक हलके में अनिश्चितता बढ़ गई है क्योंकि केंद्र ने सोमवार को भी यही दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार गठित करने के लिए भाजपा को राकांपा के 54 विधायकों का समर्थन था। केंद्र ने न्यायालय से अनुरोध किया कि राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिए उसे दो तीन दिन का वक्त दिया जाए।

वहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से हैं और पार्टी के 54 विधायकों ने उन्हें अपनी तरफ से राज्य में सरकार गठन पर निर्णय के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि परिवार में झगड़ा जल्द सुलझ जाएगा। अजित पवार की ओर से पेश अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने न्यायालय को बताया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भाजपा के साथ सरकार गठन के लिए सौंपा गया पत्र तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सही है। सिंह ने कहा, 'मैं राकांपा हूं। मैंने जो पत्र दिया, वह तथ्यात्मक रूप से सही है। पत्र का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार में जो झगड़ा है, वह जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन इस याचिका का अभी अंत होना चाहिए।' *भाषा*

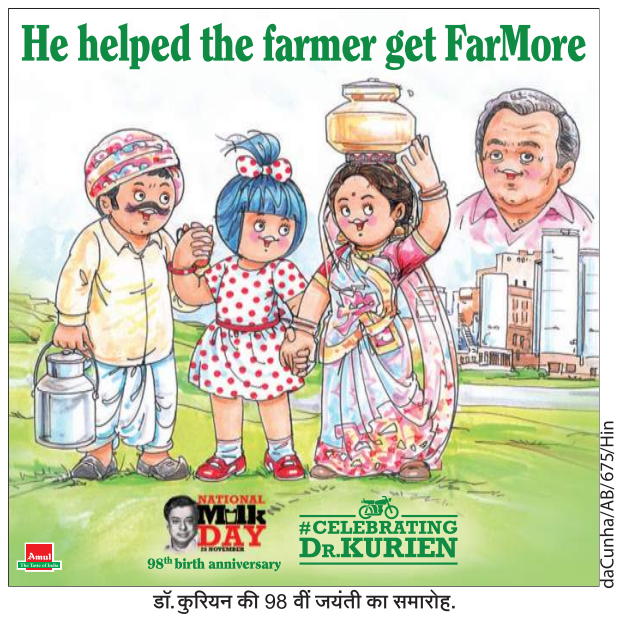

डॉ. कुरियन की 98 वीं जयंती का समारोह.

सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामले बंद किए

अजित पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को बताया कि उसने राज्य की नौ सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच बंद कर दी है। इसके साथ ही एजेंसी ने स्पष्ट किया कि ये मामले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े हुए नहीं हैं। एसीबी ने यह विपक्षी कांग्रेस के इस दावे के बाद यह सफाई दी कि दो दिन पहले सरकार बनाने में भाजपा की मदद करने की वजह से अजित पवार को दोषमुक्त कर दिया गया है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2013 में हुए सिंचाई घोटाले से जुड़े ऐसे किसी भी मामले को बंद नहीं किया गया है जिनमें कथित तौर पर अजित पवार का नाम है।

अधिकारी ने कहा कि मामले को सशर्त बंद किया गया है। इसका अभिप्राय है कि राज्य सरकार या अदालत दोबारा मामलों को खोल सकती है। उन्होंने कहा, 'अहम सिंचाई से जुड़े करीब 3,000 ठेकों की जांच कर रहे हैं, जिन मामलों को बंद किया गया है वे नियमित जांच थी और बाकी सभी मामलों की पहले की तरह जांच चल रही है।' इस मामले पर महाराष्ट्र की भाजपा-अजित पवार सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि जनहित में केवल एक फैसला लिया गया है, वह है भ्रष्टाचार और अपराध के सभी मामलों को बंद कर दिया जाए।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार ने अजित पवार से जुड़े मामलों की फाइलें बंद कर दी हैं। सरकार बनवाने की एवज में यह सब किया गया है। सिंचाई घोटाले के जिन मामलों की जांच बंद की गई, उनसे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाए।'

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'भाजपा-अजित पवार द्वारा महाराष्ट्र के प्रजातंत्र चीरहरण अध्याय की असलियत उजागर। एक नाजायज सरकार द्वारा एसीबी को मुकदमे बंद करने का आदेश दिया गया।' *भाषा*

आधार का व्यापक इस्तेमाल लेकिन दिक्कतें बरकरार

अरूप रायचौधरी

देश में 30 फीसदी बेघर लोगों और 27 फीसदी ट्रांसजेंडर के पास आधार नहीं है। इसके अलावा असम के 90 फीसदी और मेघालय के 61 फीसदी बाशिंदों के पास भी आधार कार्ड नहीं है। ये आंकड़े सलाहकार कंपनी डलबर्ग द्वारा सोमवार को जारी आधार पर सर्वेक्षण में सामने आए हैं।

यह रिपोर्ट 'आधार की स्थिति' शीर्षक नाम से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि इन कमियों के बावजूद देश में आधार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। देश में करीब 95 फीसदी वयस्क लोगों के पास आधार है और वे इसका औसतन हर महीने में एक बार कोई सेवा लेने में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में 75 फीसदी बच्चों के पास भी आधार कार्ड हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, '8 फीसदी या करीब 10.2 करोड़ लोगों के पास आधार नहीं होने का अनुमान है, जिनमें 7.5 करोड़ बच्चे हैं।'

रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस अध्ययन में आधार पर मई और सितंबर 2019 में किए गए दो राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षणों के नतीजों को परिष्कृत बनाया गया है। इन दो सर्वेक्षणों में 1,67,000 निवासियों के अनुभव और नजरिये को शामिल किया गया था, इसलिए ये आधार और व्यापकता में दुनिया में कहीं डिजिटल आईडी के इस्तेमाल पर सबसे बड़े प्राथमिक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर आधार नहीं होना व्यक्तिगत प्राथमिकता का मामला नजर नहीं आता है। जिनके पास आधार नहीं है, उनमें से ज्यादातर वयस्कों ने कहा कि हम यह पहचान-पत्र लेना चाहते हैं। इन लोगों में से ज्यादातर ने आवेदन करने की कोशिश नहीं की। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वहां स्थानीय नामांकन केंद्र नहीं थे या केंद्र बंद हो चुके थे। लोगों को पता नहीं है कि कहां नामांकन कराएं या उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों के पास आधार है, उनमें से 90 फीसदी लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि बैंक खाते के लिए आधार कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके अलावा 90 फीसदी का मानना है कि उनके ब्योरे भारतीय विशिष्ट पहचान-पत्र प्राधिकरण के पास सुरक्षित हैं। वहीं कार्ड होने के बावजूद आवश्यक सेवाओं मुहैया कराए जाने से मना किए जाने के बाद भी 67 फीसदी संतुष्ट हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'जिन लोगों ने सिम कार्ड या बैंक खाता खोलने के लिए आधार पेश किया, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी सेवा प्रदाताओं ने केवल आधार स्वीकार किया।'

जिन लोगों ने आधार को अद्यतन करने की कोशिश की, उनमें से 33 को यह प्रक्रिया जटिल लगी और हर पांच में से एक ऐसा करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस समय चार फीसदी लोगों के आधार कार्ड में उनके ब्योरे गलत हैं, जबकि 15 फीसदी लोगों के जुड़े हुए मोबाइल फोन नंबरों में गलती है। वहीं 39 फीसदी का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है।'

- सर्वेक्षण में शामिल 92 फीसदी लोग आधार से संतुष्ट
- 90 फीसदी मानते हैं कि यूआईडीएआई के पास उनका डेटा सुरक्षित
- 80 फीसदी ने माना, आधार ने पीडीएस राशन, नरेगा या सामाजिक पेंशन को ज्यादा विश्वसनीय बनाया
- 90 फीसदी लोगों में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार कानूनी रूप से अनिवार्य है
- 33 फीसदी ने कहा कि आधार के अद्यतन की प्रक्रिया जटिल थी

महाराष्ट्र का घटनाक्रम और 1984 से समानता

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के हालिया गतिरोध में 1984 के राजनीतिक घटनाक्रम से सीख सकती है सबक

आदिति फडणीस

आंध्र प्रदेश में एन टी रामा राव की तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने 1983 के विधानसभा चुनावों में 294 सीटों में से 199 जीतकर निर्णायक जीत हासिल की थी। एन टी रामा राव मुख्यमंत्री बने। वह 1984 में हार्ट सर्जरी के लिए अमेरिका गए। इसके एक समय के भीतर राज्यपाल राम लाल ठाकुर ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर तेदेपा को 'तोड़कर' एनटीआर के वित्त मंत्री नादेंडला भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया। यह ऐसी योजना थी, जिस पर कई महीनों से काम किया जा रहा था। भास्कर राव ने तेलुगू देशम के 92 (जो जल्द ही 95 हो गए), कांग्रेस (आई) के 57, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहाद-अल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पांच और चार निर्दलीय यानी कुल 158 या 161 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया।

लेकिन भास्कर राव की सूची में शामिल विधायकों में से 35 ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन बुलाया और एक स्वर में कहा कि सूची में उनके नाम धोखाधड़ी से शामिल किए गए हैं। भास्कर राव ने कहा कि उन्होंने इन 35 विधायकों समेत सभी समर्थक विधायकों को राज्यपाल के समक्ष पेश किया है। भास्कर राव के बयान से तेलुगू देशम पार्टी की युवा इकाई के तत्कालीन नेता और इन 35 विधायकों में से एक एम रत्ना बोस क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, 'भास्कर राव झूठे हैं। उन्होंने हमारी मानहानि की है और हमें अदालत जाना चाहिए।'

इसके बाद वही हुआ, जिसके आसार थे। भास्कर राव सरकार सदन के पटल पर बहुमत साबित नहीं कर पाई। राम लाल की जगह शंकर दयाल शर्मा को राज्यपाल बनाया गया, जिन्होंने एनटीआर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

इस घटनाक्रम से भास्कर राव के खिलाफ जनता में इतना रोष पैदा हो गया कि जब वह पूर्व राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी से मिलने अनंतपुर गए तो पूरे रास्ते में बांस के खंभों पर पुरानी चप्पलें टांगी गईं। तटीय आंध्र प्रदेश के उनके जिले गुंटूर में महिलाओं ने राव का स्वागत करने के लिए पुरानी झाड़ू एकत्रित की। करीमनगर जिले में जगतियल निर्वाचन क्षेत्र के सैकड़ों बाशिंदों ने उन्हें एक टेलीग्राम भेजकर वहां नहीं आने का आग्रह किया। इसके अलावा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। तब आंध्र प्रदेश ने तेदेपा के पक्ष में निर्णायक मत दिया। यह वही आंध्र प्रदेश था, जो 'इंदिराम्मा' और उनकी कांग्रेस को बहुत प्यार करता था।

राकांपा सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर बनी थी लेकिन अन्य वैचारिक पैमानों पर नहीं कांग्रेस से अलग

महाराष्ट्र के मौजूदा गतिरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए सबक छिपा है। ये सब चीजें तभी साफ होने के आसार हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला करेगा कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायकों ने विधायक दल के पूर्व नेता अजित पवार को हस्ताक्षरित पत्र दिए थे और फडणवीस सरकार को समर्थन का वादा किया था या नहीं। लेकिन इससे भी अहम मुद्दा यह है कि यह सब क्यों हुआ।

इस समस्या की जड़ राकांपा के ढांचा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 'विदेशी मूल' के होने को लेकर विरोध पर राकांपा बनी थी। अन्य वैचारिक पैमानों पर उन्हें कांग्रेस से अलग कहना मुश्किल है। अजित पवार का कद तब बढ़ा, जब उन्हें शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति संभालने का जिम्मा सौंपा। यह वह समय था, जब शरद पवार दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में व्यस्त थे। अजित को सहकारी चीनी मिलों की पेचीदा और सरपरस्ती की राजनीति का अनुभव था। वह जल्द ही उस राकांपा के दूसरे नंबर के बोस बन गए, जिसके लिए सत्ता में रहना ही एकमात्र उद्देश्य था।

यह मौका 2019 के विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को बहुमत न मिलने की वजह से आया। क्या तब भी षडयंत्र की रणनीति तैयार थी, जब बहुत से राकांपा के नेता भाजपा में शामिल हुए थे। उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण उदयनराजे भोसले का पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होना था। भोसले तीन बार राकांपा के सांसद रह चुके हैं। वह सातारा से लोक सभा सांसद हैं। वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की 13वीं पीढ़ी के वंशज हैं। वह पार्टी में अजित पवार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे। उनके पार्टी छोड़ने से राकांपा को अपने गढ़- मराठा बहुल पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। इस क्षेत्र में 70 विधानसभा सीटें हैं।

सोलापुर जिले के ताकतवर मराठा नेता विजयसिंह मोहिते-पाटिल की अजित से कटुता बढ़ गई थी और इसलिए वह राकांपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उनका मानना था कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उनका मानना था कि उन्हें विधायी दल का नेता बनाया जाना चाहिए था क्योंकि 2009 में राकांपा विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना था। इसके बजाय अजित पवार को यह पद दिया गया। इस दिग्गज राकांपा नेता और उनके बेटे रणजीत सिंह ने पार्टी छोड़ दी।

महाराष्ट्र में राकांपा के दो पूर्व अध्यक्ष- मधुकर पिचाड और भास्कर जाधव शरद पवार के वफादार सेनापति थे। इनमें से मधुकर पिचाड पार्टी छोड़कर भाजपा में और भास्कर जाधव शिव सेना में शामिल हो गए। दोनों के अजित पवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे।

पार्टी को 1 सितंबर को झटका परिवार से ही लगा। अजित पवार के साले पदमसिंह पाटिल के बेटे राणा जगजित सिंह भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल अजित जिस टेरना सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन थे, उससे जगजित सिंह ने 229 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। लेकिन अजित ने इस कर्ज से निजात दिलाने में सिंह की कोई मदद नहीं दी।

अजित पवार के बेटे पार्थ को 2019 में मावल विधानसभा क्षेत्र से राकांपा उम्मीदवार के रूप में उतारा गया, लेकिन वह शिव सेना के श्रीरंग बारने से 2,16,000 मतों से हार गए। यह साफ था कि हालांकि नई पार्टी खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार की राकांपा को लेकर ही लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाई। यह दरार अब पूरी हो गई है। आज शरद पवार लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनकी राकांपा उन्हें लौटाई जाए। यह देखना होगा कि कौन सरकार बनाता है और सत्ता में बना रहता है, लेकिन राकांपा को महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद में बदलाव करना होगा।

अजित पवार के साथ मनमुटाव के कारण राकांपा के कई नेता चुनाव से पहले पार्टी छोड़ भाजपा में हुए थे शामिल